हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 169 बेमेतरा, सोमवार 09 फरवरी 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहरों को दहलाने की साजिश

नई दिल्ली। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष आतंकी सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने दिल्ली, आगरा और ढक्कन समेत भारत के अन्य बड़े शहरों पर हमले की खुली धमकी दी है। आतंकी संगठन की ओर से दी गई यह धमकी उसकी बौखलाहट और हताशा को दर्शाती है। जानकारी के अनुसार तथाकथित 'कश्मीर सॉलिडैरिटी डे' के मौके पर जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सार्वजनिक रैलियां निकालीं। इन रैलियों के दौरान भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए और बड़े शहरों को निशाना बनाने की धमकियां दी गईं। इस दौरान सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने भारत को लेकर विवादित और उकसाने वाले बयान दिए। उसने कहा कि कश्मीर को अलग कराने के नाम पर उसका संगठन अपने पुराने मंसूबों पर कायम है और भारत के प्रमुख शहरों को निशाना बनाने की बात दोहराई।

यूट्यूबर शादाब जकाती पर रेप का केस दर्ज

मेरठ । सोशल मीडिया पर अपने डायलॉग '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी' से रातों-रात मशहूर हुए यूट्यूबर शादाब जकाती अब कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। हंसी-मजाक के वीडियो बनाने वाले शादाब पर एक महिला ने रेप, बंधक बनाने और शारीरिक शोषण जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला की शिकायत पर मेरठ पुलिस ने शादाब, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार) समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित महिला मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है और वर्ष 2016-17 में मेरठ आई थी। यहां उसने लव मैरिज की और टाइल-पत्थर की मजदूरी कर अपना गुजारा करती थी। रील बनाने के शौक के चलते वह फरवरी 2025 में अपने वीडियो के प्रमोशन के लिए शादाब जकाती के पास गई थी।

जल जीवन मिशन से 16 करोड़ घरों को मिल रहा नल से जल - सीआर पाटिल

जयपुर। लोकसभा में बजट पर प्रधानमंत्री के जवाब न देने को लेकर जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री को संसद में जवाब देना था, उसी दिन कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया कि स्थिति बिगड़ सकती थी सीआर पाटिल ने कहा कि कांग्रेस की महिला सांसदों का प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकसभा सवाल पूछने और जवाब देने का मंच है, न कि किसी को घेरने या दबाव बनाने का स्थान।

मलेशिया में द्विपक्षीय वार्ता में बोले पीएम मोदी

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मित्र देशों का साथ जरूरी

मलेशिया/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत और मलेशिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। पीएम मोदी ने मलेशिया में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात को भावनात्मक और विशेष अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों में मलेशियाई नेतृत्व के प्रति सम्मान और अपनापन साफ दिखाई देता है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की अहमियत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया दोनों इस बात पर सहमत हैं कि दोनों देशों की शांति और समृद्धि एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत और मलेशिया को मौजूदा वैश्विक हालात में अपने रिश्तों की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत और मलेशिया के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। इसके साथ ही कौशल विकास और क्षमता निर्माण में भी दोनों देश अहम साझेदार बनकर उभरे हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर भी सकारात्मक प्रगति हो रही है।

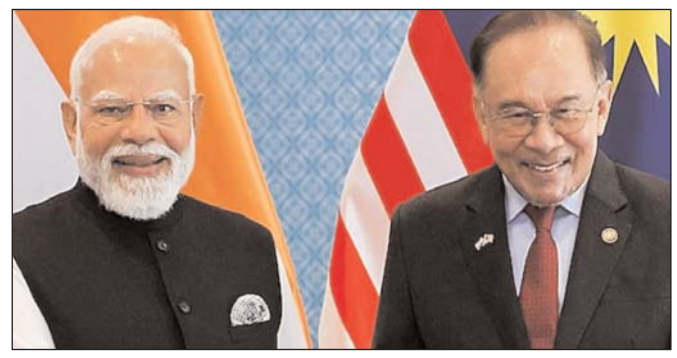

प्रधानमंत्री मोदी ने ASEAN की अध्यक्षता के लिए मलेशिया को बधाई दी और उम्मीद जताई कि मलेशिया के नेतृत्व में भारत-ASEAN संबंध और अधिक मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत-मलेशिया संबंधों की असली मजबूती लोगों के बीच के रिश्तों में दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि मलेशिया में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनकी मलेशिया की तीसरी यात्रा है और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से उनकी चौथी मुलाकात, जो दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ती निकटता को दर्शाती है। उन्होंने बीते वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में आई गति और गहराई के लिए मलेशियाई नेतृत्व का आभार जताया। पीएम मोदी ने मलेशिया में मिले गर्मजोशी भरे और पारंपरिक स्वागत के लिए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और उनकी सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिस सुंदर तरीके से मलेशियाई संस्कृति और जीवनशैली को प्रस्तुत किया गया, वह हमेशा यादगार रहेगा। वहीं, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिन्हें दोनों देशों की टीमें आगे बढ़ाएंगी।

आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की जरूरत

पीएम मोदी ने कहा, कल मुझे आपके डायस्पोरा से मिलने का अवसर मिला, और यह एक खास अनुभव था। मैंने देखा कि आपके लिए डायस्पोरा में कितना सम्मान और लगाव है, जो मुझे गर्व महसूस कराता है। आतंकवाद के खिलाफहमारी लड़ाई में दोस्त देशों का समर्थन बहुत जरूरी है। हमारा पक्का विश्वास है कि भारत और मलेशिया की खुशहाली एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में, भारत और मलेशिया के लिए अपने रिश्तों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि उनका उद्देश्य भारत और मलेशिया के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है और हर संभव क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।

राउत का सलमान और आरएसएस पर हमला

भाईजान सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए बुलाए गए थे.....?

नई दिल्ली। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े कार्यक्रम में सलमान खान समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुईं। संजय राउत ने इस पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या सलमान खान को सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया था? उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल किया कि क्या यह कदम सिर्फ यह दिखाने के लिए है कि अब संघ में मुसलमानों का स्वागत है? राउत ने यह भी दावा किया कि कई लोग वहां अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दबाव में गए थे। संजय राउत ने अपनी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि उद्धव जी को फिर से विधान परिषद में लौटना चाहिए। राउत के अनुसार, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके उद्धव ठाकरे की मौजूदगी राज्य के लोगों और विपक्ष की मजबूती के लिए विधानसभा में बहुत जरूरी है। यह पूरे महा विकास अघाड़ी गठबंधन की इच्छा है।

प्रशांत किशोर की बिहार नवनिर्माण यात्रा शुरू

बगहा से भरी हुंकार, मोदी-नीतीश को याद दिलाया महिलाओं से किया 2-2 लाख रूपए का वादा...

पटना/ एजेंसी

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रविवार, 8 फरवरी को उन्होंने पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से अपनी 'बिहार नवनिर्माण यात्रा' की औपचारिक शुरुआत की। पीके ने स्पष्ट किया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर जिले में जाकर जन सुराज के संगठन का पुनर्गठन करना और पार्टी की नींव को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाना है। चुनाव के बाद यह उनका पहला बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। अपनी यात्रा के पहले दिन प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव से पहले किया गया 'महिला रोजगार योजना' का वादा याद दिलाया। पीके ने कहा कि अगर एनडीए सरकार महिलाओं को 2-2 लाख रुपये देने की अपनी घोषणा को अमलीजामा नहीं पहनाती है, तो यह साफहो जाएगा कि यह केवल वोट बटोरने का एक जरिया था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर महिलाओं को यह राशि नहीं मिली, तो जन सुराज जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि वे हर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान न केवल पुराने साथियों

के साथ बैठकें होंगी, बल्कि समाज के नए और ऊर्जावान लोगों को भी जन सुराज पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। उनका लक्ष्य पार्टी के ढांचे को नए सिरे से तैयार करना है ताकि भविष्य की चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके। पीके ने जोर दिया कि उनकी पार्टी अब पूरी तरह से संगठन को धार देने पर फोकस कर रही है। चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए पीके ने कहा कि बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता ने एनडीए को सत्ता और आरजेडी को विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं, जन सुराज के लिए जनता ने यह तय किया है कि हम समाज के बीच रहकर उनके बुनियादी मुद्दों पर काम करें। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ निभाएगी। पीके के इस बदले हुए तेवर से साफहै कि वे आने वाले समय में बिहार की सियासत में अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहते।

शिवराज सिंह चौहान ने गिनाए सुरक्षा चक्र

अमेरिकी उत्पादों के लिए बंद रहेंगे भारत के दरवाजे-चौहान

नई दिल्ली/ एजेंसी

एक तरफ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत-अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के लिए स्वर्णिम अवसर बता रहे हैं, वहीं किसान संगठनों ने 12 फरवरी को इस डील के विरोध में 'भारत बंद' और प्रदर्शन की चेतावनी दी है। समझिए कृषि मंत्री की प्रेस कांफ्रेंस में क्या-क्या खास रहा। भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते ने देश की राजनीति और कृषि क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। जहां केंद्र सरकार इसे भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार

खोलने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और किसान संगठनों ने इसे 'किसान विरोधी' करार दिया है। इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभालते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय किसानों का हित 'सर्वोपरि' है और उनके अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया गया है।शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों को समझौते से बाहर रखा गया है। सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज और दलहन (मूंग, काबुली चना) जैसे प्रमुख अनाजों पर टैरिफ में कोई छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा, डेयरी क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए अमेरिका से लिक्विड दूध, घी, मक्खन, पनीर, योगर्ट और क्रीम जैसे उत्पादों की एंट्री पर रोक बरकरार रखी गई है।

हाईकोर्ट का अहम फैसला : बालिगों को शादी के लिए परिवार या समाज की मंजूरी जरूरी नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि लड़का-लड़की यदि अपनी स्वतंत्र इच्छा और आपसी सहमति से विवाह करना चाहते हैं, तो इसके लिए न तो परिवार और न ही समाज की मंजूरी आवश्यक है। अदालत ने कहा कि जीवनसाथी चुनना व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हिस्सा है, जिसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने कहा कि विवाह करना व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद और आज़ादी से जुड़ा विषय है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अधिकार है।

एसआईटी का बड़ा धमाका!

गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

असम/ एजेंसी

असम में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) की जांच में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के कथित पाकिस्तानी संपर्कों को लेकर कई अहम और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एसआईटी ने इस मामले में पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख को मुख्य कड़ी (हैंडलर) के रूप में चिह्नित किया है। अली तौकीर शेख पाकिस्तान के योजना आयोग का सलाहकार बताया जा रहा है। एसआईटी के अनुसार, अली तौकीर शेख एलिजाबेथ

गोगोई का करीबी सहयोगी है और उसने ही 'लीड पाकिस्तान' नाम की एनजीओ की स्थापना की थी। यही वह संगठन है, जहां कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई ने काम किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि शेख सोशल मीडिया पर भारत के आंतरिक मामलों, संसद और राजनीतिक मुद्दों पर लगातार टिप्पणी करता रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि अली तौकीर शेख की ऑनलाइन गतिविधियां भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने के इरादे को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती हैं। शेख बार-बार भारत की घरेलू राजनीति और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर राय देता रहा है।एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अली तौकीर शेख ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों और थिंक टैंक नेटवर्क के जरिए भारत में अपने संपर्कों का दायरा बढ़ाया।

केंद्रीय गृह मंत्री की समीक्षा बैठक में बस्तर पर खास फोकस

नक्सलवाद से विकास की ओर छत्तीसगढ़-केंद्रीय गृहमंत्री शाह

रायपुर/ संवाददाता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में वामपंथी उग्रवाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति और बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सुरक्षा, प्रशासन और विकास से जुड़े कई अहम पहलुओं पर मंथन हुआ। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का केंद्र माना जाता था, वह आज भाजपा की डबल इंजन सरकार के तहत विकास का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा अब खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा

के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने, नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने और प्रभावित इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र को आदिवासी संभाग के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सके। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि विकास और सुरक्षा की रणनीति साथ-साथ आगे बढ़े, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित हो सके। इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल,आईबीपी के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक सहित छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बस्तर पंडुम समापन समारोह में 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि

रायपुर। बस्तर की जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समर्पित तीन दिवसीय बस्तर पण्डुम का समापन समारोह 9 फरवरी को एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह विशेष तौर पर शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे। 'प्रकृति और परंपरा का उत्सव' के ध्येय वाक्य के साथ मनाया जा रहा यह आयोजन बस्तर की माटी की खुशबू और यहां की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम है। इस गरिमामयी समापन समारोह का आयोजन 9 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से लालबाग मैदान जगदलपुर में निर्धारित है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े शामिल होंगे। बस्तर पण्डुम में सांसद द्वय श्री महेश कश्यप और श्री भोजराज नाग, विधायक श्री किरण सिंहदेव, सुश्री लता उसेंडी, श्री विनायक गोयल, श्री नीलकंठ टेकाम, श्री विक्रम उसेंडी, श्री आशाराम नेताम, श्री चैतराम अटामी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्री लखेश्वर बघेल, श्री विक्रम मंडावी, महापौर श्री संजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

ग्राम पंचायत टकसीवा में रोजगार दिवस के साथ आवास दिवस का आयोजन

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वंचित परिवारों को पक्के आवास दिलाने पर दिया गया जोर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बेमेतरा जिले के जनपद पंचायत बेरला अंतर्गत ग्राम पंचायत टकसीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रत्येक वंचित परिवार को पक्के आवास का लाभ दिलाने तथा आवास निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 7 फ़रवरी 2026 को रोजगार दिवस के साथ आवास दिवस का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रेमलता पदमाकर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान आमजन को ङ्कक्क त-क्रक्र्ल्त एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं, पात्रता, लाभ एवं समयबद्ध निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आवास दिवस मनाने के पीछे शासन की मंशा यह है कि प्रत्येक आवास हितग्राही की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन कर उन्हें समय पर आवश्यक संसाधन, तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके, जिससे आवास निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो सके। कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों के आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई तथा निर्माण में आ रही विभिन्न समस्याओं जैसे सामग्री की उपलब्धता, तकनीकी कठिनाइयों एवं मजदूरी से संबंधित मुद्दों का तत्काल समाधान किया गया। हितग्राहियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर पंचायत पदाधिकारी, ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनपद पंचायत बेरला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से सहायक अभियंता, प्रोग्राम ऑफिसर, ब्लॉक समन्वयक, तकनीकी सहायक, आवास मित्र एवं रोजगार सहायक की सक्रिय सहभागिता रही।कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों में आवास एवं रोजगार योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध हुआ।

लोक कला महोत्सव एवं रंग महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

विधानसभा, अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरिया, सिलघट(भी) एवं लावातरा (ढा) मे जय मां शारदा सेवा व झांकी मंडली एवं विभिन्न समितियो द्वारा आयोजित लोक कला महोत्सव एवं रंग महोत्सव में पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, उपस्थित हुए इस अवसर पर पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि जैसा की लोक कला महोत्सव एवं रंग महोत्सव हमारे धार्मिक संस्था का एक प्रमुख केंद्र है तथा गांव में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है जिससे हमें सीख मिलती है कि अपने गांव में भाईचारा एकता , बनाए रखने के लिए लोक महोत्सव एवं रंग महोत्सव पर्व का त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है लोक कला तथा जस गायन के रूप में हम अपनी संस्कृति को समृद्ध करते हैं तथा रंग महोत्सव सतनाम समाज इससे न केवल आपसी भाईचारा बढ़ता है बल्कि गांव में रौनकता भी आती है शक्ति की आराधना पूरे संसार में की जाती है और इसी शक्ति के आराधना आज हमारे ग्राम में हो रही है जो अत्यंत ही हर्ष का विषय है तथा आयोजन समिति को मैं इसके लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इस अवसर पर रवि परगनिहा सुमित राजपूत शुभम वर्मा सीमा टिकरिहा हिरेंद्र बघेल ओनी महिलांग मनीष बंजारे रामसिंग गायकवाड खेमलाल वर्मा प्रवीणचंद सुराना जोईधा राम वर्मा संदीप टिकरिहा लोकनाथ यादव परमेश्वर निषाद नकुल निषाद कुंजलाल निषाद कुंभकरण विश्वकर्मा तोरण सेन रामकिशुन वर्मा जगदीश रावत दयाराम वर्मा बिरऊ निषाद लाला वर्मा लखन निषाद सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे ।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बहेरा में 'परीक्षा पे चर्चा 2026' का सीधा प्रसारण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षा तनाव से मुक्त रहने का दिया मंत्र

बेमेतरा/मूक पत्रिका

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बहेरा, जिला बेमेतरा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के 9वें संस्करण का सीधा प्रसारण सफलतापूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा से जुड़े तनाव से मुक्त करना तथा उन्हें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा की तैयारी हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना था।विद्यालय परिसर में आयोजित इस लाइव प्रसारण को विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों ने भी एकाग्रता के साथ देखा और सुना। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा जीवन का केवल एक छोटा सा पड़ाव है, इसे कभी भी भय या तनाव का कारण नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे स्वयं की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी क्षमताओं को पहचानें और निरंतर प्रयास करते रहें।प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, नियमित अभ्यास एवं स्वस्थ दिनचर्या अपनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि संतुलित दिनचर्या, योग, खेलकूद और पर्याप्त विश्राम विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री किशोर कुमार दहिकर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 'परीक्षा पे चर्चा' जैसे कार्यक्रम छात्रों को मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संवाद विद्यार्थियों को परीक्षा को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देते हैं, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से उन्हें परीक्षा को लेकर सकारात्मक सोच मिली है। छात्रों ने इस सत्र को अत्यंत प्रेरणादायक, उपयोगी और मार्गदर्शक बताया, जिससे उन्हें आगामी परीक्षाओं की तैयारी में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के आदेश पर अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी ने जताया आभार, मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेताओं को कहा धन्यवाद

डोंगरगांव/मूक पत्रिका

प्रधानमंत्री आवास योजनाङ्कशहरी 2.0 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने हेतु जारी किए गए शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देशों पर नगर पंचायत अध्यक्ष डोंगरगांव अंजू त्रिपाठी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है।

अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी ने इस जनहितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू, कैबिनेट मंत्री श्री तोखन साहू एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का हृदय से धन्यवाद किया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनाङ्कशहरी 2.0 के अंतर्गत पात्रता को लेकर जारी किए गए स्पष्ट दिशा-निर्देशों से उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो कच्चे, जर्जर अथवा आपदा से प्रभावित मकानों में रहने को मजबूर हैं। अब सही पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ पहुंचेगा।

नगर पंचायत अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी ने कहा कि नगर निकायों को दी गई जिम्मेदारी से योजना का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी होगा तथा ÷हर गरीब को पक्का मकान÷ का सपना साकार होगा।

÷प्रधानमंत्री आवास योजनाङ्कशहरी 2.0 के तहत जारी दिशा-निर्देश गरीबों के लिए बड़ी राहत हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, कैबिनेट मंत्री श्री तोखन साहू जी एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूँ।÷

अंजू त्रिपाठी, नगर पंचायत अध्यक्ष डोंगरगांव

मंगलवार की जगह अब हर सोमवार लगेगा कलेक्टर जनदर्शन

सूरजपुर/मूक पत्रिका

जिला प्रशासन ने आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और प्रशासनिक कार्यों की बेहतर समीक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर जनदर्शन के आयोजन दिवस में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब 09 फ़रवरी से जनदर्शन मंगलवार के स्थान पर प्रत्येक सोमवार को आयोजित किया जाएगा।

सोमवार को ही होंगी अहम विभागीय समीक्षा बैठकें- जनदर्शन के साथ ही प्रत्येक सोमवार को समय-सीमा की बैठक, राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा समिति, एनकॉरड (ह्र्रूह्रञ्जष्ठ), छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा दोषमुक्ति प्रकरणों से संबंधित बैठकों का आयोजन भी पूर्व निर्धारित समय पर किया जाएगा। इसके अलावा पास्को अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक भी सोमवार को आयोजित होगी।

आमजन से जनदर्शन में शामिल होने की अपील-जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं, शिकायतों और मांगों के समाधान के लिए सोमवार को आयोजित होने वाले जनदर्शन में उपस्थित होकर इस व्यवस्था का लाभ उठाएं।

सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर फ्रॉड करने वाले आरोपी गिरफ्तार

कांकेर/मूक पत्रिका

उत्तर बस्तर कांकेर ब्लॉक भानुप्रतापपुर में दिनांक 2 फ़रवरी 2026 को थाना भानु प्रतापपुर में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके मोबाइल नंबर में अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया, इसके पश्चात मोबाइल धारक के द्वारा प्रार्थी को वीडियो फ़ोटो वायरल करने की धमकी देकर लगभग 84000 रुपये ठगी कर लिया गया है कि रिपोर्ट पर थाना भानुप्रतापपुर में अपराध पंजीबद किया गया, मामले की गंभीरता को देखते हुए निखिल राखेचा पुलिस अधीक्षक जिला उत्तर बस्तर के निर्देशन में आकाश श्रीमाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर के मार्गदर्शन में शेर बहादुर सिंह ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भानुप्रतापपुर के पर्यवेक्षण में थाना भानुप्रतापपुर एवं साइबर सेल से आरोपी पता तलाश हेतु टीम रवाना किया गया जो छत्तीसगढ़ पुलिस एवं राजस्थान पुलिस के समन्वय से अलवर राजस्थान से पकड़ा गया आरोपी के द्वारा अपराध कबूल करने एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 08.02.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक निर्माण पर भेजा गया, प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक प्रेम कुमार झा, प्रधान आरक्षक ,सचिन शोरी, प्रधान आरक्षक , विजय कटकवार, आरक्षक ,प्रणय यादव का विशेष योगदान रहा है। कांकेर पुलिस की अपील अपराध पर नियंत्रण पुलिस और जनता की साझा जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से जिला उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस द्वारा किसी भी संदिग्ध अपराधिक गतिविधियों की जानकारी देने के लिए अपराधिक हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 संचालित की जा रही है यहां दी गई हर सूचना एवं सूचनाकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है ।

आर. वी. ब्यूटी पार्लर का भव्य शुभारंभ, जिला अध्यक्ष राजालाल बंजारे ने किया फीता काटकर उद्घाटन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बीते रविवार 09 फ़रवरी 2026 को सिरवाबांधा रोड स्थित शासकीय आत्मानंद शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के सामने आर. वी. ब्यूटी पार्लर का भव्य शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज बेमेतरा के जिला अध्यक्ष राजालाल बंजारे ने फीता काटकर पार्लर का विधिवत उद्घाटन किया।इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संगठन के संरक्षक लखन लाल टोंडरे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भुवनदास जांगड़े, सचिव देवीचंद डेहरे एवं कोषाध्यक्ष हिरेश टंडन मान सिंह बंजारे , जलेश्वर बंजारे, लछन टंडन, संतोषी टंडन की गरिमामयी उपस्थिति रही।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने आर. वी. ब्यूटी पार्लर संचालक को नए व्यवसाय की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे प्रयास न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह ब्यूटी पार्लर आधुनिक सुविधाओं एवं बेहतर सेवाओं के माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं को लाभान्वित करेगा। शुभारंभ अवसर पर पार्लर को आकर्षक रूप से सजाया गया था तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, शुभचिंतक एवं समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। उक्त जानकारी ब्यूटी पार्लर के संचालक अमित टंडन ने दिया।

तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस में हुआ व्यापक शैक्षणिक संवाद, प्रान्त संघचालक एवं पूर्व शिक्षा सचिव रहे अतिथि वक्ता, 104 शोध सारांश का हुआ प्रकाशन

समाधान महाविद्यालय में एनईपी-2020, सतत शिक्षा एवं मानवीय चेतना पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श

बेमेतरा/मूक पत्रिका

सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति द्वारा संचालित समाधान महाविद्यालय, बेमेतरा में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (हृश्वक्क2020), सतत शिक्षा एवं मानवीय चेतना विषय पर एक विशेष पैरेलल सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का विषय सस्टेनबल एजुकेशन फॉर ह्यूमन एन्ड प्लेनटेरी वेलबीइंग रहा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविदों, नीति विशेषज्ञों एवं विषय-विशेषज्ञों ने सहभागिता की। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रांत संघचालक डॉ. टोपलाल वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित स्व-आधारित जीवन शैली को शिक्षा के केंद्र में लाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा को केवल कौशल या रोजगार तक सीमित न रखकर चेतना, संस्कार और आत्मनिर्भर सोच से जोड़ा जाना चाहिए। कीनोट सत्र में वक्ताओं ने एनईपी-2020 के विभिन्न आयामों पर विचार रखे। डॉ. शारदा शर्मा (अम्बा दीदी), अमरकंटक ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः धनोपार्जन पर केंद्रित हो गई है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य मानव को सही कार्य-व्यवहार और संबंधों की समझ देना होना चाहिए।पूर्व कुलपति डॉ. अरुणा पल्टा ने बताया कि एनईपी-2020 का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों का बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं चरित्रगत विकास करना है तथा सतत शिक्षा एवं मूल्यांकन मानव और विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है।रजिस्ट्रार डॉ. भूपेंद्र कुलदीप ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए शिक्षा, ज्ञान और चेतना का एकीकरण अनिवार्य है।डॉ. संकेत ठाकुर ने स्पष्ट किया कि सतत विकास तभी संभव है जब मानवीय चेतना का विकास हो, अन्यथा विकास अस्थायी रह जाता है।डॉ. अशोक ठाकुर, डायरेक्टर, मुनि इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को विधिपूर्वक लागू करने से विद्यार्थियों में चेतना जागृत होती है तथा सहयोग की भावना विकसित होती है, जिससे छात्र स्वयं समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनते हैं। नंदकुमार डी. जी., आईएएस, पूर्व शिक्षा सचिव ने कहा कि भविष्य की शिक्षा का आधार स्व-अध्ययन, पीयर लर्निंग, जिज्ञासा, तकनीकी उपयोग और सीखने की गति के अनुसार वातावरण निर्माण होना चाहिए। इसके लिए सशक्त नेतृत्व और सही प्रबंधन आवश्यक है।डॉ. राकेश मुद्गल, कुलपति आत्मीय विश्वविद्यालय, गुजरात ने कहा कि ज्ञान से क्षमता, मूल्यों से दिशा और नैतिकता से कार्यवाही निर्धारित होती है।डॉ. सुरेंद्र पाठक ने विज्ञान, अध्यात्म और मानवीय चेतना के एकीकरण को सतत विकास की आधारशिला बताया। अन्य वक्ताओं में सुशील कुमार राठौर ने एनईपी-2020 के संदर्भ में मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।श्रीमती अनीता शाह एवं चानी चावड़ा ने चेतना विकास आधारित मूल्य शिक्षा को एनईपी-2020 के लक्ष्यों की पूर्ति का प्रभावी माध्यम बताया।अंकित पोगुला ने जीवन के लक्ष्य की स्पष्टता को शिक्षा का मूल उद्देश्य बताया।डॉ. अंजली औधिया ने विज्ञान और नैतिकता के समन्वय को आवश्यक बताते हुए कहा कि दोनों मिलकर ही मानव मूल्यों को दिशा दे सकते हैं। सम्मेलन में 104 शोध सारांशों का प्रकाशन, प्रोसीडिंग बुक का विमोचन तथा शैक्षणिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पैनल एक्सपर्ट के रूप में प्रो. विद्यानंद पाण्डेय एवं डॉ. बृजेश प्रताप यादव उपस्थित रहे। प्रतिभागियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के डायरेक्टर एवं सचिव डॉ अवधेश पटेल एवं सहायक प्राध्यापक हरीश कुमार पटेल ने किया तथा अंत में महाविद्यालय के डायरेक्टर श्री अविनाश तिवारी ने आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष सीता वर्मा में स्वागत किया। सम्मेलन में बेमेतरा जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए 150 से अधिक शिक्षकों, सहायक प्राध्यापकों, रिसर्च स्कॉलर की सहभागिता रही।

खटिया पर जिंदगी: सड़क के अभाव में कंधों पर उठाकर ले जानी पड़ी बीमार महिला

कुछ दूरी पर एम्बुलेंस, लेकिन सड़क नहीं : आदिवासी गांव की दर्दनाक तस्वीर

कुसमी/मूक पत्रिका

बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत बालापानी गांव की यह तस्वीर केवल एक बीमार महिला की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर करारा तमाचा है, जो गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के दावे करती है। बालापानी गांव में एक गंभीर रूप से बीमार महिला को चार ग्रामीणों ने खटिया पर बैठाकर कंधों पर उठाया, जबकि एक अन्य व्यक्ति खाने-पीने का सामान लेकर कई किलोमीटर पैदल चलकर लक्ष्मणपुर तक पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि 1 घंटा से ऊपर हुए पैदल चलकर एम्बुलेंस के पास आना पड़ा अगर सड़क सही होती तो, एंबुलेंस गांव तक पहुंच सकती, मगर सड़क अच्छी नहीं होने के वजह से हमें खाटी और कंधे पर बोह के लाना पड़ा। अगर कोई अत्यंत बीमार हो और लेकर जाना पड़े अचानक तो हमें कई मुसीबत झेलनी पड़ेगी।कारण साफ है—गांव तक आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई।सड़क नहीं होने के कारण 108 एम्बुलेंस सेवा गांव के भीतर नहीं जा सकी। मजबूरी में ग्रामीणों ने मरीज को कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, तब जाकर उसे अस्पताल ले जाया जा सका। महिला के पूरे शरीर में सूजन थी और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। हर पल की देरी जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन यहां जिंदगी से बड़ी समस्या ÷सड़क÷ बनकर सामने खड़ी हो गई।

कागजों का विकास, जमीन पर बदहाली–सरकार प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचाने के दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि बालापानी गांव में आज भी लोग कंधों पर जिंदगी ढोने को मजबूर हैं। यह गांव आदिवासी बृजिया समाज का है, जहां आज भी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है।बरसात के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। कीचड़ और दुर्गम रास्तों के कारण पैदल चलना मुश्किल हो जाता है और एम्बुलेंस पहुंचना नामुमकिन। सवाल यह है कि क्या ऐसे गांव सिर्फ सरकारी आंकड़ों और भाषणों तक ही सीमित रह जाएंगे?

सड़क नहीं तो विकास नहीं — ग्रामीणों की आर-पार की मांग–ग्रामीणों का साफ कहना है कि सड़क नहीं तो विकास नहीं।

कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, आवेदन दिए गए और अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन नतीजा अब तक शून्य ही रहा। आज एक बीमार महिला की पीड़ा ने उस सच्चाई को उजागर कर दिया है, जिसे अब तक कागजों में दबाया जाता रहा।यह घटना केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि उस सोच पर भी सवाल खड़े करती है, जहां दूरस्थ आदिवासी गांवों की समस्याएं प्राथमिकता नहीं बन पातीं। बालापानी गांव आज पूछ रहा है—क्या हमारी जिंदगी की कीमत एक सड़क से भी कम है?

प्रशासन का पक्ष–इस मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक पांडेय ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए- बताया कि गांव तक जाने के लिए कच्चा मार्ग मौजूद है, जिससे ट्रैक्टर और अन्य चार पहिया वाहन आते-जाते हैं। हालांकि, घाटी और चढ़ाई होने के कारण एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाती।

शासन को भेजा गया प्रस्ताव, मंजूरी का इंतजार,सीईओ पांडेय ने आगे बताया कि- बालापानी गांव के लिए सड़क निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।

यह घटना एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब प्रशासन के सामने स्पष्ट चुनौती है—या तो इस दर्द को सुने और सड़क निर्माण को प्राथमिकता दे, या फिर विकास के दावों पर उठते सवालों का सामना करे।

उपसंचालक कृषि द्वारा सेवा सहकारी समिति बुंदेला एवं गिरदावरी कार्यों का निरीक्षण

भौतिक सत्यापन कर अभिलेखों की जांच, पारदर्शिता व गुणवत्ता पर दिया गया जोर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कृषि विभाग द्वारा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज 07 फरवरी 2026 को उपसंचालक कृषि श्री मोरध्वज डड़सेना द्वारा जनपद नवागढ़ अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बुंदेला का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण के दौरान उपसंचालक कृषि ने समिति में संधारित अभिलेखों, भंडारण व्यवस्था, किसानों को प्रदत्त सेवाओं तथा विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुपालन की गहन समीक्षा की। उन्होंने समिति के माध्यम से किसानों को समय पर बीज, खाद एवं अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आगामी कृषि मौसम में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके पश्चात उपसंचालक कृषि द्वारा ग्राम सेमरिया (नवागढ़) में गिरदावरी एवं डीसीएस सर्वे कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फसल क्षेत्र, बोनी की स्थिति, फसल प्रकार एवं गिरदावरी प्रविष्टियों की मैदानी जांच की गई तथा अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन किया गया। उन्होंने गिरदावरी कार्य को पूरी गंभीरता, सटीकता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को फसल बीमा, समर्थन मूल्य एवं अन्य योजनाओं का लाभ सही रूप में मिल सके। निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक कृषि श्री देशराज यादव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नांदघाट एवं छ्ष्टस सर्वेयर उपस्थित रहे। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान आवश्यक जानकारी प्रदान की तथा उपसंचालक कृषि के मार्गदर्शन में कार्यों की प्रगति से अवगत कराया।उपसंचालक कृषि श्री डड़सेना ने अधिकारियों एवं मैदानी अमले को निर्देशित किया कि सभी कृषि संबंधित कार्य पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं किसान हित को सर्वोपरि रखते हुए संपादित किए जाएं। उन्होंने कहा कि नियमित निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन से विभागीय योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों का विश्वास भी सुदृढ़ होता है।

28.19 करोड़ की सड़क परियोजना को स्वीकृति, भटगांव क्षेत्र में विकास को मिलेगी नई गति

सूरजपुर/भटगांव/मूक पत्रिका

भटगांव विधानसभा क्षेत्र के सड़क विकास को लेकर राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बीरपुर 12 मील हनुमान मंदिर (सिलफिली) से कालीघाट महावीरपुर (अंबिकापुर) तक राष्ट्रीय राजमार्ग‌43 के डामरी मजबूतीकरण कार्य के लिए 28.19 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना से लंबे समय से जर्जर सड़क की समस्या के समाधान की उम्मीद बढ़ी है।

जर्जर सड़क से मिलेगी राहत, आवागमन होगा सुगम–उक्त मार्ग की खराब स्थिति के कारण क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों और यात्रियों को लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क के मजबूतीकरण कार्य से आवागमन सुरक्षित और सुविधाजनक होगा तथा दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।

व्यापार, परिवहन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा–सड़क निर्माण और मजबूतीकरण से भटगांव विधानसभा सहित आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। परिवहन व्यवस्था बेहतर होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अंबिकापुर जैसे प्रमुख शहरी केंद्र से संपर्क मजबूत होने से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर–क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सड़क परियोजना को भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक बेहतर होगा। यह परियोजना पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है तथा यातायात व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सुचारु हो सकेगी।

ग्राम पंचायत गोपालपुर में मानव श्रृंखला के साथ रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का भव्य आयोजन

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का गृह प्रवेश, अधूरे आवास वाले हितग्राहियों को किया गया प्रेरित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जनपद पंचायत साजा अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर में रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का भव्य एवं प्रेरणादायी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत बेमेतरा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रेमलता पद्माकर रहीं। आयोजन का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों में गति लाना, हितग्राहियों को प्रोत्साहित करना तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के पूर्ण हो चुके आवासों के लाभार्थियों को चाबी वितरण कर विधिवत गृह प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों को सम्मानित किया गया, जिससे अन्य हितग्राहियों को भी समय पर आवास निर्माण पूर्ण करने की प्रेरणा मिली। साथ ही ड्क्कल-क्रूल एवं आवास योजना के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया, जो कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा।जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं, उन्हें गुलाब का फूल भेंट कर प्रोत्साहित किया गया तथा शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों को यह भी बताया गया कि समय पर निर्माण पूर्ण करने पर किस्तों की राशि सुचारु रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

आवास दिवस और रोजगार दिवस के उद्देश्य पर दिया गया विशेष जोर

आवास दिवस के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा हितग्राहियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। वहीं रोजगार दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को ड्क्कल-क्रूल के मुख्य उद्देश्य की जानकारी दी गई तथा यह समझाया गया कि यह योजना भविष्य में किस प्रकार रोजगार के अवसर सृजित करने, ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती प्रेमलता पद्माकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। इन योजनाओं के माध्यम से जहां एक ओर ग्रामीणों को पक्के आवास की सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और निरंतर प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक पात्र परिवार को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके 7 कार्यक्रम में जिला पंचायत के अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के कर्मचारी, पंचायत पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। उपस्थित जनसमुदाय ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं रोजगार गारंटी योजना के तहत हो रहे कार्यों की सराहना की और इनके सफल क्रियान्वयन हेतु अपना सहयोग व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया गया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया गया, जिससे कार्यक्रम और भी उत्साहपूर्ण बन गया।

जानबुझ कर तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट करने से गिरफ्तार किया

आरोपी द्वारा शराब सेवन कर चलाया जा रहा था वाहन कार को

कांकेर/मूक पत्रिका

प्रार्थी नरोत्तम साहू पिता जगनाथ साहू उम्र 40 वर्ष निवासी पोटगांव के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, इसका भाई अपने मोटर साइकिल से ग्राम कोदागांव से पोटगांव आ रहा था जो पीछे से आ रही मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 19 सी 0316 का चालक द्वारा शराब सेवन कर ठोकर मारकर एक्सीडंट करने से मृत्यु होने की रिपोर्ट पर थाना कोरर में मर्ग क्रमांक 14/2026 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही मे लिया गया। मर्ग जांच में पर से आरोपी चालक के विरूद्ध अपराध क्रमं कि 20/2026 धारा 281, 106 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 07.02.2026 को वाहन क्रमाक सीजी 19 सी 0316 के चालक द्वारा अपने वाहन को जानबुझ कर तेजगति एवं लापरवाही जानते हुए कि, अधिक रफ्तार वाहन चलाने से किसी को ठोकर लगने से मृत्यु होना संभव है फिर भी अपने वाहन को जानबुझ कर तेज गति से चलाते हुए ग्राम कोदागांव । पोटगांव के बीच एक मोटर सायकल को ठोकर मारातत्पश्चात् वहां से भागते हुए एक अन्य मो0सा0 को पीछे से ठोकर मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।धारा 105 बी.एन. एस. एवं आरोपी द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाने पर प्रकरण में अतरिक्त धारा 185 एम. व्ही एक्ट जोड़ी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए निखिल राखेचा पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में, योगेश साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर के मार्ग दर्शन में, मोहसिन खान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर के पर्यवेक्षण में, थाना कोरर द्वारा विषेष टीम गठित की जाकर आरोपी के बारे में पता तलाश हेतु रवाना हुई।प्रकरण में विवेचना के दौरान गवाहां का कथन लेखबद्ध किया गया जो पाया गया कि, आरोपी नवाज अली निवासी संजय नगर कांकेर के द्वारा दिनांक यह जानते हुए कि, शराब सेवन कर वाहन को जानबूझ कर तेज रफ्तार चलाकर एक्सीडेंट करने से किसी का मृत्यु होना संभव है फिरभी अपने वाहन कार क्रमाक सीजी 19 सी 0316 को तेज रफ्तार चलाकर एक्सीडेंट करने से प्रकरण मं आरोपी को गिरफ्तार कर दिनाँक 08/02/2026 को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। पुलिसटीम छत्रपाल सिंह साहू, लकेश रावटे, योगेश मंडावी, विनोद साहू, दुवारू मंडावी, भारत दुग्गा, मनोज साहू, तिलक मेश्राम, ईश्वर कावड़े एव अन्य स्टॉफका सहयोग रहा ।

सतनामी समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

फिजूलखर्ची को छोड़कर परम् पूज्य गुरु घासीदास बाबा के बताये सादगी विवाह को गर्व के साथ अपनाने की जरूरत : कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

रायपुर /मूक पत्रिका

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्री एवं सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहेब का रविवार को सारंगढ़ प्रवास रहा, जहाँ कैबिनेट मंत्री प्रदेश स्तरीय सतनामी समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निरंतर सतनामी समाज के लिए किए जा रहे सबका साथ सबका विकास के कार्यों, प्रदेश में गुरु घासीदास बाबा के मेला आयोजन के लिए स्वीकृत राशि का अपने संबोधन में जिक्र किया। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि, बाबा गुरु घासीदास के सादा जीवन, उच्च विचार के जो संदेश दिए गए हैं जो संस्कृति और संस्कार बताए गए हैं, उसके सादगी विवाह की परम्परा को हमें गर्व के साथ अपनाने की जरूरत है। आगे गुरु साहेब जी ने कहा कि, जिस प्रकार आज हम दिखावे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिखावे की शादी में धन का खर्च बहुत ज्यादा है। लड़का ढूंढना है या लड़की ढूंढना है तो हम सब लोगों को कितना परेशानी होती है। आज लोग विवाह को सम्मान और इज्जत के रूप में देखते हैं और मन मुताबिक शादी करते हैं भले ही कर्ज लेना पड़े। दिखावे से थोड़ा उठके हमें सादा विवाह की राह बहुत पहले परम् पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने दी है। इसमें किसी प्रकार का खर्च नही है। समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना स्थापित करें। **राज्य सरकार द्वारा परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के मेला आयोजन के लिए राशि स्वीकृत**–मंत्री गुरु साहेब ने कहा कि, गिरौधपुरी हो, भंडारपूरी हो,चाहे लालपुर धाम हो, हर जगह के लिए करोड़ों रुपए पैसा स्वीकृत है। किसी प्रकार के कोई कमी नहीं है सिर्फ धार्मिक स्थल की उन्नति और विकास है। सारंगढ़ में प्रतिवर्ष बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी ने इसके लिए राशि स्वीकृत की है जो आजतक चल रही है। आज मात्र 2 साल के अंदर में मुख्यमंत्री जी ने हमारा हमेशा लगातार सहयोग किया है। शिक्षा के स्तर में भी सीजीपीएससी में एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, उसकी फ्री कोचिंग की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र से सर्व समाज के उन्नति और विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी कार्य कर रहे हैं।इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी,कार्यकर्ता एवं सतनामी समाज के पदाधिकारी,कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में युवक युवती, पालक, सतनामी विकास परिषद के सदस्य और पत्रकारगण उपस्थित थे।

संपादकीय

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से राहत की उम्मीद, पर कई सवाल अब भी बाकी

पिछले कई महीने से अमेरिका की ओर से लागू शुल्क नीति के कारण जहां दुनिया भर में व्यापार युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही थी, वहीं भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश करने की थी। अब सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उससे यही लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच परस्पर हित पर आधारित एक समझौता आकार ले सकता है।ट्रंप ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका-भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत शुल्क को पचास फीसद से घटा कर अठारह फीसद किया जाएगा। दूसरी ओर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भी इसी तरह अमेरिका के खिलाफ अपनी शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दोनों देशों की ओर से ऐसी घोषणा को शुल्क के मसले पर महीनों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और भारत की नीतियों में अब एक बड़े बदलाव का सूचक माना जा रहा है। हालांकि यह साफ होना बाकी है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अंतिम तौर पर किस स्वरूप में सामने आता है और उसमें बनी सहमति कहां तक परस्पर हित सुनिश्चित करती है। मगर फिलहाल सामने आई खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने जिस तरह शुल्क में कमी करने की बात कही है, उसके अमल में आने पर भारत को राहत मिल सकती है।दरअसल, कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर अमेरिकी नीतियों का असर पड़ना शुरू हो चुका था। इसके बावजूद भारत ने अमेरिका की ओर से जरूरत से ज्यादा सख्त शर्तों की वजह से समझौते के लिए सहमति देने को लेकर सावधानी बरती और इससे उपजी मुश्किल का विकल्प तलाशने की कोशिश जारी रखी। यही वजह है कि अमेरिका की ओर से शुल्क को पचास फीसद कर देने की घोषणा के बाद भी भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी। यों ट्रंप ने दावा किया है कि अब भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से कहीं अधिक मात्रा में तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से भी तेल खरीद पर सहमति जताई है। हालांकि भारत और रूस के बीच जैसे संबंध रहे हैं, उसके मद्देनजर यह देखने की बात होगी कि रूस से तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने के सवाल पर भारत क्या रुख अपनाता है।इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाने का एक बड़ा कारण यह था कि भारत कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोलने को लेकर राजी नहीं था। व्यापार समझौते के अंतिम रूप में भारत कृषि जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या हासिल करता है, लेकिन किसानों की ओर से कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं।

जहां तक इस कुत्सित सोच की वैधानिक न्यायसंगतता के आधार का सवाल है तो भारतीय संविधान समानता (अनुच्छेद 14-16) और सामाजिक न्याय पर जोर देता है, लेकिन अतीत के अपराधों के लिए वर्तमान निर्दोषों को 'सजा' देना प्रतिशोधात्मक लगता है, जो अबतलक बदस्तूर जारी है। अतीत के भेदभाव को आधार बनाकर सवर्ण समाज के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को दंडित करने या आरक्षण जैसी नीतियों से बांधना न्यायसंगतता के सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत योग्यता को नजरअंदाज कर सामूहिक दोषारोपण करता है। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि अतीत में हुए भेदभाव पर सवर्णों के वर्तमान-भविष्य को कानूनी शिकंजे में कसना दलित-ओबीसी नेतृत्व की न्यायसंगतता का तकाजा नहीं है!

अतीत में हुए भेदभाव पर सवर्णों के वर्तमान-भविष्य को कानूनी शिकंजे में कसना न्यायसंगतता का तकाजा नहीं?

(कमलेश पांडे)

लिहाजा, उन्मुक्त हृदय से उनके मौजूदा प्रगतिशील नेताओं को गहराई पूर्वक विचार करना चाहिए और अपने पूर्वजों के प्रतिगामी नजरिए को बदलकर स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के राष्ट्रव्यापी लोकतांत्रिक भाव को मजबूत करना चाहिए। अन्यथा सामाजिक विघटन को परमाण्विक प्रक्रिया तेज होगी और इससे पैदा हुए जनविद्वेष की आग में देर-सबेर हरेक शांतिप्रिय लोगों के भी झुलसने का आसन्न खतरा बना रहेगा। ऐसा इसलिए कि यह नीतिगत, वैधानिक और रणनीतिक सवाल है जिसे कूटनीतिक स्वार्थवश विदेशों से हवा दी गई, इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, जिससे जातिविहीन हिंदुत्व के राष्ट्रवादी विचार को गहरा धक्का लगा है।

जहां तक इस कुत्सित सोच की वैधानिक न्यायसंगतता के आधार का सवाल है तो भारतीय संविधान समानता (अनुच्छेद 14-16) और सामाजिक न्याय पर जोर देता है, लेकिन अतीत के अपराधों के लिए वर्तमान निर्दोषों को 'सजा' देना प्रतिशोधात्मक लगता है, जो अबतलक बदस्तूर जारी है। इसलिए कहीं न कहीं यह सामाजिक एकता को कमजोर करता प्रतीत होता है। वहीं, जहां तक इस आशय की हुई क्षतिपूर्ति की अवधारणा की बात है तो यह अतीत-वर्तमान के अंतर्संबंध पर आधारित है, परंतु यह तब न्यायपूर्ण होती है जब यह पीड़ितों को शक्ति प्रदान करे, न कि नए भेदभाव को जन्म दे।

खासकर भारतीय संदर्भ में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी*ओबीसी) आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय सुधारने का ब्रितानी और भारत सरकार का विषैला सियासी प्रयास है, किंतु यूजीसी बिल (2026) जैसे नए प्रतिगामी नियमों व

कदमों के दुरुपयोग की आशंका पैदा करते हैं, जहां झूठे आरोप सामाजिक कड़वाहट बढ़ा सकते हैं। यह ठीक है कि रोहित वेमुला या पायल तडवी जैसे मामले दर्दनाक हैं, लेकिन नीतियां ऐसी हों जो योग्यता और समावेश को प्राथमिकता दें।

ऐसा इसलिए कि एक तो छात्र राजनीति से पढ़ाई-लिखाई पर आंच आई, विश्वविद्यालय कैम्पस की गरिमा गिरी है और अब उन्हें जातीय नजरिए से बांटना आग से खेलने जैसा मूर्खता भरा सियासी कदम है। इससे सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की तरह ही जातिवादी राष्ट्रवाद की भावना को बल मिलेगा।

इसलिए बेहतर होगा कि हमारा सत्ता प्रतिष्ठान वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित करे। मेरे विचार से शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक उत्थान से भेदभाव दूर करना अधिक न्यायसंगत है, क्योंकि संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने से भविष्य स्वाभाविक रूप से समान बनेगा।

कहना न होगा कि अतीत को याद रखना जरूरी है, किंतु वर्तमान को उसके बोझ से मुक्त रखना ही सामाजिक प्रगति का आधार है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिन्नावादी सांप्रदायिक सोच से निरंतर झुलस रहे भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रितानी और अंबेडकरवादी/लोहियावादी जातिवादी सोच से विखंडित करने का जो मूर्खतापूर्ण सरकारी प्रयास जारी है, उससे जब सत्तर साल बाद भी मुट्ठीभर दलित-आदिवासी-ओबीसी की ही भलाई हो पाई है और उनमें भी नवसामंती भावना प्रबल हुई है, जिससे विखंडित जनादेश आने से अवसरवाद बढ़ा है। यह भारत के समावेशी विकास में भी अब बाधक बनता प्रतीत होता है।

यह ठीक है कि भारत में जातिगत भेदभाव के लिए

क्षतिपूर्ति मुख्यतः सकारात्मक कार्रवाई के रूप में लागू होती है, जो ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास करती है। क्योंकि यह आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और विधायी सुरक्षा के माध्यम से कार्य करती है। इस हेतु संवैधानिक प्रावधान भी नियत हैं।भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, 16, 46 और 335 के तहत एससी/एसटी/ओबीसी को शिक्षा, नौकरियों और विधायी सुरक्षा प्रदान करता है, जो भेदभाव रोकने और उत्थान सुनिश्चित करने के लिए हैं। वहीं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। जबकि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अपराधों पर दंड और पीड़ितों को राहत देता है।

आरक्षण सम्बन्धी प्रमुख नीतियां भी स्पष्ट हैं। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण एससी को 15 प्रतिशत, एसटी को 7.5 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत कोटा नियत है। इसी आधार पर उन्हें छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। उन्हें पोस्ट-मैट्रिक, प्री-मैट्रिक और अन्य योजनाएं वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। वहीं, कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वरोजगार ऋण, कौशल विकास और आवास योजनाएं (जैसे अंबेडकर आवास योजना) से भी उन्हें लाभान्वित किया जाता है। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब सवर्णों को भी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, लेकिन अन्य सहूलियत उन्हें मिलना अभी बाकी है। हालांकि, भारत की जातिवादी आरक्षण वाली सोच के समक्ष कुछ मजबूत चुनौतियां भी हैं। अगड़े भारतवासी इन्हें जाति की बजाए आर्थिक करने की मांग निरंतर करते आये हैं। वैश्विक नजरिए से भी ये नीतियां दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका जैसे देशों की क्षतिपूर्ति से भिन्न हैं, जहां प्रत्यक्ष आर्थिक मुआवजा दिया जाता है; जबकि भारत में फोकस सशक्तिकरण पर है, लेकिन इसके दुरुपयोग और सामाजिक तनाव की अकसर आलोचना होती है। सवाल है कि आखिर ऐतिहासिक भेदभाव या उत्पीड़न क्या है? तो जवाब होगा कि ऐसे ऐतिहासिक भेदभाव या उत्पीड़न से तात्पर्य उन सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रक्रियाओं से है जो लंबे समय से चली आ रही हैं और जिनके कारण कुछ समूहों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया। यह अक्सर जाति, नस्ल, लिंग या धर्म जैसे आधारों पर आधारित होता है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी सामाजिक संरचनाओं में निहित हैं। वहीं, उत्पीड़न इसके हिंसक या शोषणकारी रूप को दर्शाता है, जैसे बहिष्कार या हिंसा। इस प्रकार ऐतिहासिक भेदभाव किसी विशिष्ट विशेषता (जैसे जाति या नस्ल) के आधार पर समूहों के साथ जानबूझकर भिन्न व्यवहार है, जो पीढ़ियों तक चलता रहता है। भारत में यह जाति व्यवस्था से जुड़ा है, जहां दलितों को मंदिर, पानी या शिक्षा से वंचित रखा गया था। भारत में इसके लिये अकसर सवर्ण समाज खासकर ब्राह्मणों को आरोपित किया जाता है, जबकि सनातनी ब्राह्मणों ने तो उन्हें धार्मिक रूप से भी हिंदुत्व की माला में पिरोया है और उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की है। जबकि मुस्लिम काल और अंग्रेजी काल में उनके हुए उत्पीड़न व शोषण से इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि भारत सरकार में भी इस्लामिक व ब्रिटिश सत्तागत सोच वाली बुराइयों को निरंतरता प्रदान की गई है, जो बहस का विषय है। उदाहरणस्वरूप, जातीय उत्पीड़न को ही लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दलितों पर शारीरिक हिंसा, यौन शोषण या सामाजिक बहिष्कार, जो औपनिवेशिक काल से चला आ रहा, निंदनीय है। वहीं, नस्लीय भेदभाव का भी यही आलम है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति या अमेरिका में रेडलाइनिंग, जहां नस्ल के आधार पर ऋण अस्वीकार किए गए। कुछ वैसा ही घटनाक्रम भारत में भी चला ब्रिटिश प्रभाव वश। वहीं, उपनिवेशिक प्रभाववश मुगलिया और ब्रिटिश राज में भारतीय अभिजात वर्ग को भी भेदभाव का शिकार बनाया गया, जो सामाजिक विषमता को गहरा करने वाला था। यह भेदभाव आज भी असमानता को बनाए रखता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार में अवसरों की कमी। कानूनी उपाय जैसे भारत का संविधान (अनुच्छेद 15, 17) इसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भारत में भेदभाव रोकने के लिए संविधान और विभिन्न कानून प्रमुख भूमिका निभाते हैं, खासकर जाति, नस्ल या लिंग आधारित ऐतिहासिक भेदभाव के खिलाफ। ये प्रावधान समानता सुनिश्चित करते हैं और दंडनीय अपराध बनाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म-जाति-लिंग आदि पर भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत सुनिश्चित करते हैं। वहीं, कुछ प्रमुख कानून भी बनाए गए हैं। जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955= अस्पृश्यता या छुआछूत को दंडनीय बनाता है। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989= अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त प्रावधान। इसी सिलसिले की अगली कड़ी लष्ट विनियम, 2026 है, जिससे उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव रोकने के नए नियम बनाये गए हैं। जहां तक इनके कार्यान्वयन की बात है तो ये कानून अदालतों द्वारा लागू होते हैं, जैसे इंद्रा साहनी मामले में आरक्षण को मान्यता। शिकायत के लिए समर्पित सेल और पोर्टल उपलब्ध हैं। यूजीसी बिल पर भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश विचारणीय है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक है)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

गांव-गांव घूमकर भारत को समझते रहे मार्क टली

(राजेश प्रियदर्शी)

भारत में बीबीसी की पहचान रहे सर मार्क टली का जाना दुखद है। बीबीसी परिवार के लिए तो मानो पितामह के गुजर जाने जैसा है। मेरी खुशकिस्मती है कि उनसे कई बार मिलने और बातें करने का अवसर मिला, लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ी ज्यादा खुशकिस्मत थी, जिसने उनको और ज्यादा करीब से, उनकी सक्रियता वाले दौर में देखा।

मार्क टली पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन कुछ महीनों पहले तक हिन्दुस्तान टाइम्स में उनका कॉलम देखकर यह आश्वस्ति होती थी कि वह ठीक हैं। उनसे सीखने लायक अनेक बातों में से एक बात तो यही थी कि मार्क टली हर किसी से, हर समय सीखते रहते थे। भारत के समाज और राजनीति की उनकी समझ बहुत गहरी थी, लेकिन वह अक्सर अपने वाक्य की शुरुआत कुछ यूं करते, 'मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं, आप बताइए कि...।' जिन बातों की उन्हें पक्की जानकारी होती थी, उनके बारे में भी वह यही कहते थे, 'जहां तक मुझे मालूम है...।'

मुझसे कई बार वह झारखंड के बारे में पूछते थे। मार्क टली से बात करते हुए डर कभी नहीं लगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ज्ञान के आतंक की जगह विनम्र विद्वता की आभा थी, लेकिन इस बात का एहसास मुझे हमेशा रहता था कि वह संथालों और मुंडाओं के बारे में उतना ही जानते थे, जितना उत्तर प्रदेश के निषादों और बिहार के मुसहरों के बारे में या फिर केरल के पानियन या मुथुवन लोगों के बारे में। उनकी किताब नो फुल स्टॉप इन इंडिया हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, जो भारत को गहरे समझना चाहता है। वह सबसे पहले अच्छी तरह यही समझाते हैं कि भारत समझ में क्यों नहीं आता? टली ने एक ब्रितानी अर्थशास्त्री के हवाले से कहीं लिखा था- 'भारत के बारे में जो आप सच कह सकते हैं, उसके ठीक विपरीत बात भी सच होती है।'

तकरीबन 90 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मे मार्क टली हर तरह से एक खांटी हिन्दुस्तानी थे। ज्यादातर समय खादी के कुरते और सैंडल पहनने वाले टली साहब लंबे समय तक दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहे और धूप में घूमते रहने के कारण उनका गोरा रंग एक उम्र के बाद लगभग तांबई हो गया था। कोई अनजान आदमी उन्हें देखकर एकबारगी यह नहीं कह सकता था कि वह अंग्रेज हैं।

कई दशकों तक भारत और दक्षिण एशिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर शानदार पत्रकारिता करने वाले मार्क टली को आपातकाल के दौरान उनकी रिपोर्टिंग के कारण कुछ समय के लिए यहां से निकाल दिया गया था। वह लगातार निडर, लेकिन संतुलित पत्रकारिता करते रहे। मेरे बीबीसी पहुंचने से तीन साल पहले ही1994 में उन्होंने इस संस्थान से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह लगातार सक्रिय बने रहे। मार्क टली ने कोई दस किताबें लिखी हैं, जो बहुत ही दिलचस्प और पठनीय हैं।

मेरी उनसे पहली लंबी बातचीत सन् 2001 के कुंभ मेले के दौरान हुई थी। तब उन्होंने बहुत विस्तार और गहराई से समझाया कि विदेशी लोग कुंभ मेले में क्यों खिंचे चले आते हैं? किसी भी विषय पर मार्क टली से बात करने का मतलब समझ की एक नई खिड़की का खुलना होता था। उन्होंने भारत को गांव-गांव घूमकर समझा था। वह हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहना चाहते थे, जो उनको 'फर्स्ट हैंड' जानकारी दें। वह दिल्ली में संपादकों और बड़े पत्रकारों से जानकारी लेने में कम ही यकीन रखते थे। एक और बात, जो उन्हें विलक्षण बनाती थी, वह थी सहृदयता। मैंने कभी मार्क टली के मन में किसी के प्रति कटुता या दुराव का भाव नहीं देखा। उनको पसंद करने वालों की संख्या लाखों में थी, क्योंकि उन्हें नापसंद करने का कोई वास्तविक कारण खोजना मुश्किल काम था। मार्क टली को जैसी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा मिली, वह शायद ही किसी और पत्रकार को नसीब हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तित्व को सेलिब्रिटी होने की सहज संभावना से दूर रखा। मार्क टली से हर मुलाकात के बाद यह विस्मय रह जाता था कि वह इतने अद्भुत कैसे हैं? एक ऋषि जैसा जीवन जीकर विदा हुए सर मार्क टली को श्रद्धांजलि! (लेखक वरिष्ठ संपादक, बीबीसी हैं) (ये लेखक के अपने विचार हैं)

सांसद निधि की तुलना दूसरी योजनाओं से नहीं हो सकती

सांसद स्थानीय विकास निधि को लेकर इन दिनों एक वितंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों कुछ सांसदों के बारे में दावा किया गया कि उन्होंने इस मद का एक रुपया भी खर्च नहीं किया। इसी आधार पर कई लोग दलील दे रहे हैं कि इस योजना को ही खत्म कर देना जाना चाहिए, मगर सच यह है कि इसकी ऐसी उपयोगिता है, जिसकी विकास की अन्य योजना निधियों से तुलना नहीं की जा सकती। इसे व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। इसका कारण है। देश की आधारभूत संरचनाओं में प्रगति अब ठोस यथार्थ बन चुकी है। सड़क, पानी, बिजली, नाली, सीवर आदि जो कल तक स्थानीय लोगों की ज्वलंत समस्याएं हुआ करती थीं और लोग उसके समाधान की अपेक्षा सांसद-विधायक विकास निधि से रखते थे, वह बात अब प्रायः नहीं रही। पंचायत से लेकर जिले तक का बजट पिछले दस वर्षों में कई गुना बढ़ा है।

(राकेश सिन्हा)

यहां एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है। दुनिया के सभी पदों के पास घोषित शक्तियां होती हैं और पद के अनुपात में उनका विशेषाधिकार रहता है, परंतु सांसद के पास शक्ति शून्य है। वह जनता की वैधानिक ताकत से प्रतिनिधि बनता है, जनता के जीवन के सभी आयामों से उसका सरोकार होता है। अतः सांसद की ताकत विशेषाधिकार के गर्भ से उपजता है। सांसद निधि इसी विशेषधिकार को रेखांकित करता है।

इसके उपयोग में जितनी प्रयोगधर्मिता होगी, परिणाम उतने ही प्रभावी होंगे। एक उदाहरण देना चाहूंगा। बिहार के बेगूसराय के एक छोटे-से मुहल्ले (टोला) में सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिये के लोग रहते हैं। युवाओं से संवाद में पुस्तकालय-निर्माण की मांग उठी। इसकी घोषणा करके राशि आवंटित कर देना एक मिनट का काम था। मैंने ऐसा नहीं किया। घंटों अनौपचारिक संवाद चलता रहा। उसी सिलसिले में टोले का जातिसूचक नाम बदलने पर राय बनी। नया नाम तय हुआ-हनुमान-शिव टोला। मैंने पाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों

में पुस्तकालयों के प्रति आकर्षण है। एक पुस्तकालय पीढ़ियों की सोच के निर्माण का पवित्र स्थल है, जहां अध्ययन, चिंतन, सृजन और संकल्प निर्माण होता है। पुस्तकालय भौतिकता, अनैतिकता, संकीर्णता आदि से उत्पन्न आपदाओं से समाज को बचाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, खेल के प्रति उन्होंने युवाओं में उत्साह बढ़ाया है। खेल में भी सुनहरा करियर है, गांव-कस्बों तक यह संदेश गया है। अतः खेल-सुविधाओं की भी मांग अब सांसदों से होने लगी है। चाहे निर्माण या विकास का रूप जो भी हो, इसमें बहुआयामी संवाद का जरिया बनने की असीम क्षमता है। सांसद निधि के साथ नैतिकता का आयाम लगते ही उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। एक तरफ, निर्माण कार्य होता है, दूसरी तरफ संकीर्णता की दीवार ढहने लगती है। सूची बनाकर विकास योजनाओं को जारी करना या मांग के आधार पर आवंटन की अपनी उपयोगिता है, पर वे जिलाधिकारी की योजना की तरह हो जाती हैं। उससे सांसद निधि का सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष अंकुरित भी नहीं हो पाता है।

मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में कोंगथोंग गांव को मैंने 2020 में गोद लिया था। सेंगखासी (जनजाति) का स्कूल सरकारी सहायता से वंचित था। सहायता देने से पूर्व लोगों के सामूहिक श्रमदान, स्वच्छता अभियान आदि पर संवाद होते रहे। ऐसे में, सांसद निधि स्कूल के विकास से अधिक वहां सामूहिकता के भाव को आगे बढ़ाने का माध्यम बन गई। श्रमदान द्वारा निधि का उपयोग हुआ। सुखद बात यह रही कि ईसाई और सेंगखासी समुदायों के बीच चली आ रही कटुता मिट गई।

हमारे लोकतंत्र में एक कमी है, सांसदों के कार्यकलापों, विशेषकर सांसद निधि के उपयोग का सोशल ऑडिटिंग न होना। यह 'सब धान बाईस पसेरी' कर देता है। सोशल ऑडिटिंग से उनकी कमियों पर प्रभावी अंकुश लग सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ जनादेश नहीं है। इसकी बुनियाद में नैतिक व्यवस्था है। इसलिए सांसद निधि का उपयोग रचनात्मक तरीके से होना चाहिए। (लेखक पूर्व सदस्य, राज्यसभा) (ये लेखक के अपने विचार हैं)

संक्षिप्त समाचार

गोंदिया एवं छपरा जंक्शन के मध्य एक फेरे के लिए होली स्पेशल ट्रेन की सुविधा

बिलासपुर। आगामी होली त्यौहार के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष 1,410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की योजना बनाई गई है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से भी 15 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा ।इसी कड़ी में रेलवे द्वारा होली के अवसर पर मार्ग गोंदिया-छपरा जंक्शन की गाड़ियों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन गोंदिया एवं छपरा के मध्य एक फेरे के लिये की जा रही है । यह ट्रेन गोंदिया से गाड़ी संख्या 08863 तथा छपरा से गाड़ी संख्या 08864 के साथ चलेगी । इस गाड़ी में 02 एसएलआर, 10 सामान्य, 08 स्लीपर, 01 एसी श्री, 01 एसी टू सहित कुल 22 कोचों के साथ रवाना होगी । 08863 गोंदियाङ्कछपरा होली स्पेशल गोंदिया से दिनांक 01 मार्च, 2026 तथा 08864 छपराङ्कगोंदिया होली स्पेशल छपरा से 03 मार्च, 2026 को छुटेगी ।

आगामी होली त्यौहार के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु भारतीय रेल द्वारा रिकॉर्ड संख्या में होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन

बिलासपुर। आगामी होली त्यौहार के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष अपने नेटवर्क पर रिकॉर्ड संख्या में 1,410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की योजना बनाई गई है, जिसे बढ़ाकर लगभग 1500 ट्रेनों तक किया जाएगा। इन विशेष ट्रेनों का संचालन त्यौहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए प्रमुख गंतव्यों के मध्य बेहतर एवं सुचारु संपर्क सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। ये विशेष ट्रेनें मुख्यत: मार्च माह में संचालित की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि होली 2025 के दौरान कुल 1,144 स्पेशल ट्रेन फेरे संचालित किए गए थे। क्षेत्रवार परिचालन के अनुसार मध्य रेलवे द्वारा 209, पश्चिम रेलवे द्वारा 231, पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सर्वाधिक 285 तथा दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा 160 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसी प्रकार उत्तरी रेलवे द्वारा 108 एवं उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 71 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 66, उत्तर पूर्व रेलवे एवं पूर्व तटीय रेलवे द्वारा 62-62, दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा 47 तथा पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा 43 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दक्षिण रेलवे द्वारा 39, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 15, कोंकण रेलवे द्वारा 9 तथा उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे द्वारा 2 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। भारतीय रेल प्रमुख त्यौहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठा रही है।

असंगठित श्रमिकों को मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन

बिलासपुर। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पात्र श्रमिकों को प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को 15 मार्च तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया लोक सेवा केन्द्र या च्वाईस सेंटरों से की जा सकती है। श्रम विभाग के अधिकारी ने बताया कि 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन प्राप्त होगी। जो हितग्राही 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होगा उसको प्रतिमाह 55 रुपये के मान से 60 साल की उम्र होते तक हर महीने 55 रुपये जमा करना होगा। इस हिसाब से वह कुल 27720 रुपये जमा करेगा। 60 वर्ष का होते ही उसको पहले ही साल में 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से एक ही साल में कुल 36000 रुपये मिल जायेगा, अर्थात एक ही साल में पैसा वसूल हो जायेगा। 18 से 40 वर्ष उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह के काम एवं रोजगार में संलग्न है और जिसकी आय 15000 रुपये मासिक से कम हो योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। लघु-व्यापारी एवं स्वरोजगारी के अंतर्गत नाई, धोबी, मोची, दर्जी, पान दुकान वाला, छोटे-मोटे किराना दुकान, छोटा मोटा होटल वाला, चाय दुकान वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका वार्षिक 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर हो और आयकर रिटर्न शून्य हो। कामगार या श्रमिक के अंतर्गत घर काम वाली बाई, कोई भी नौकर नौकरानी, रिक्शावाला, ऑटोवाला, फेरीवाला, रेजा-कुली, नल मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, टाइल्स मिस्त्री, बढ़ई, हमाल, सफाई वाला स्वीपर, पोताई करने वाला, सरकारी ऑफिस में दैनिक वेतनभोगी, पानी पिलाने वाला, रसोईया, चौकीदार, सुरक्षा गार्ड, राउत, दूध पहुँचाने वाला, चरवाहा, मछली पकड़ने वाला मछुवारा, पेपर वाला हॉकर, कचरा बिनने वाले, मनरेगा के श्रमिक, स्वसहायता समूह की महिलायें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, मितानिन, आशा कार्यकर्ता भी सभी योजना के लिए पात्र होंगे।

डबल इंजन सरकार की बड़ी सौगात

तोखन साहू के प्रयासों से बिलासपुर एयरपोर्ट अब ऑल-वेदर संचालन के लिए तैयार है....

बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट को xC-VFR âð xC-All Weather Operations (IFR) श्रेणी में उन्नत किए जाने की स्वीकृति छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व की उपलब्धि है। इस निर्णय से अब बिलासपुर एयरपोर्ट पर सभी मौसमों में विमान संचालन संभव हो सकेगा, जिससे क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं विश्वसनीय हवाई सेवाएँ उपलब्ध होंगी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापु जी के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की विकासपरक सोच वाली डबल इंजन की सरकार के परिणामस्वरूप आज छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य संभव हो रहे हैं। केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन हेतु रक्षा मंत्रालय से आवश्यक भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय एवं निरंतर संवाद एक महत्वपूर्ण कड़ी रही, जिसके कारण यह बहुप्रतीक्षित परियोजना साकार हो सकी।. उन्होंने कहा कि ऑल-वेदर (ड्डस्रक्र) संचालन की सुविधा मिलने से अब कोहरे, वर्षा अथवा खराब मौसम की स्थिति में भी विमानों का सुरक्षित संचालन संभव होगा, जिससे उड़ानों के निरस्तीकरण में कमी आएगी और यात्रियों का समय व सुविधा दोनों सुरक्षित रहेंगे। यह उन्नयन न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे संभाग और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए व्यापार, उद्योग, निवेश और पर्यटन के नए द्वार खोलेगा। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति प्राप्त होगी। केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने विश्वास व्यक्त किया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में विकास, कनेक्टिविटी और निवेश का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।--

चिकित्सा विभाग,दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सामग्री प्रबंधन,स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं क्रय प्रक्रिया पर अंतर्विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

बिलासपुर। स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल प्रणाली को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सामग्री प्रबंधन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं क्रय प्रक्रिया विषयों पर एक अंतर्विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य डेटा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता को और अधिक सशक्त बनाना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सामग्री एवं संसाधन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संसाधनों एवं सामग्रियों के प्रभावी प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की सही एवं समयबद्ध प्रविष्टि, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन तैयार करने तथा क्रय प्रक्रिया को डिजिटल मंच पर पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही डेटा की शुद्धता, पारदर्शिता एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को आधुनिक डिजिटल साधनों एवं प्रणालियों के बेहतर उपयोग की व्यावहारिक समझ प्राप्त हुई, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं की योजना निर्माण, निगरानी एवं निर्णय प्रक्रिया को अधिक सटीक, प्रभावी एवं समयबद्ध बनाया जा सकेगा। चिकित्सा विभाग, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं को डेटा-आधारित, पारदर्शी एवं अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल है।

परीक्षा पे चर्चा 2026 : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संवाद से विद्यार्थियों को मिला आत्मविश्वास, दिशा और प्रेरणा

बिलासपुर। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत करने, परीक्षा के तनाव को दूर करने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के उद्देश्य से परीक्षा पे चर्चा-2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। पूरे जिले भर के शासकीय स्कूलों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बच्चों ने तन्मयता से सुना। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय टांडे, जिला मिशन समन्वयक श्री ओम पांडेय, समग्र शिक्षा के समस्त सहायक परियोजना समन्वयक (एपीसी), विकासखंड बिल्हा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शहरी स्रोत समन्वयक सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।कार्यक्रम के दौरान परीक्षा पे चर्चा का सजीव प्रसारण देखा गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उन्हें परीक्षा को जीवन का उत्सव मानने की सीख दी। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के मन की बात को सहजता से सुनते हुए परीक्षा की तैयारी, परीक्षा के समय तनाव की स्थिति, बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में संतुलन, सीमित संसाधनों में सफलता प्राप्त करने के उपाय, खेल और शिक्षा के बीच सामंजस्य, साथ ही वर्तमान समय में तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सकारात्मक उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरल, व्यावहारिक और प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान किया।

सजगता से टली संभावित दुर्घटनाएँ-07 संरक्षा प्रहरियों को मंडल रेल प्रबंधक ने किया सम्मानित

बिलासपुर। संरक्षित रेल परिचालन रेलवे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु मंडल स्तर पर संरक्षा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ड्यूटी के दौरान सजगता एवं सतर्कता का परिचय देते हुए संभावित दुर्घटनाओं को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 07 संरक्षा प्रहरियों को सम्मानित किया गया। अकलतरा के गेटकीपर श्री भूपेंद्र कुमार तथा बाराद्वार के यातायात सहायक श्री जगदीश प्रसाद ने मालगाड़ियों में हॉट एक्सल की पहचान कर समय रहते सूचना देकर गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित की। वहीं बिलासपुर के लोको पायलट श्री मुकेश कुमार एवं सहायक लोको पायलट श्री कुमार पल्लब तंबोली ने जांजगीर नैला स्टेशन पर सजगता दिखाते हुए ट्रेन का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया। इसी प्रकार हिमगीरङ्कदाघोरा सेक्शन में वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर रायगढ़ श्री भूपेंद्र कुमार ने धुआँ एवं जलने की गंध महसूस होने पर त्वरित कार्रवाई कर संभावित दुर्घटना टाली। मड़वारानी स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधक श्री अनुज कुमार एवं वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर श्री सिद्धिनाथ यादव ने गाड़ी के नीचे लटक रहे लोहे के पैनल को हटाकर सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित किया। इन सभी कर्मचारियों के सराहनीय कार्य के लिए वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी श्री साकेत रंजन द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार हेतु अनुशंसा की गई। आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक श्री राकेश रंजन ने सभी संरक्षा प्रहरियों को संरक्षा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। इस अवसर पर वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी श्री साकेत रंजन उपस्थित थे।

बिलासपुर स्टेशन में चला किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान

- 361 मामलों में 1लाख 88 हजार 40 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

बिलासपुर। टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने, बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी रोक लगाने तथा यात्रियों को रेलवे नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल द्वारा बिलासपुर स्टेशन में किलाबंदी टिकट चेकिंग एवं रायगढ़ - बिलासपुर-भाटापारा स्टेशनों के मध्य ट्रेनों में गहन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री डी.एस. चौहान के निर्देशन में आज 05 फरवरी 2026 को चलाया गया। अभियान में वाणिज्य निरीक्षक, मुख्य टिकट निरीक्षक, टीटीई स्टाफ व रेलवे सुरक्षा बल सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। अभियान के दौरान बिलासपुर स्टेशन एवं रायगढ़ - बिलासपुर-भाटापारा स्टेशनों के मध्य गुजरने वाली 20 ट्रेनों में सघन टिकट जांच की गई। इस दौरान कुल 361 मामलों से 1,88,040 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया। इनमें बिना टिकट यात्रा के 288 मामलों से 1,62,340 रुपये, अनियमित टिकट के 52 मामलों से 23,010 रुपये तथा बिना बुक किए गए लगेज के 21 मामलों से 2,690 रुपये का जुर्माना शामिल है। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा के लिए उचित एवं वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें तथा स्टेशन परिसर में प्रवेश से पूर्व प्लेटफार्म टिकट अवश्य खरीदें। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुटओवर ब्रिज का ही उपयोग करें। रेलगाड़ी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने में रेल प्रशासन का सहयोग करें। इस प्रकार के अभियान आगे भी जारी रहेंगे, जिससे रेलवे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान किया जा सके।

छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रगति

7,470 करोड़ का बजट अनुदान, 51,080 करोड़ की रेल परियोजनाएँ प्रगति पर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल अधोसंरचना के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को निरंतर गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को ?7,470 करोड़ का बजट अनुदान प्रदान किया गया है। इस अनुदान के माध्यम से राज्य में रेल संपर्क को मजबूत करने, यात्री सुविधाओं में सुधार, माल परिवहन क्षमता बढ़ाने तथा सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में ?51,080 करोड़ की लागत की रेल परियोजनाएँ विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नई रेल लाइनों का निर्माण, अतिरिक्त लाइनों का विकास, स्टेशनों का पुनर्विकास, रेल संरक्षा कार्य तथा आधुनिक तकनीक आधारित अवसंरचना का विकास किया जा रहा है, जिससे राज्य के औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को निरंतर बल मिल रहा है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित प्रमुख रेल परियोजनाओं में बिलासपुरङ्कझारसुगुड़ा चौथी लाइन परियोजना शामिल है, जिसकी कुल लंबाई 206 किलोमीटर तथा लागत ?2,135.34 करोड़ है। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक 175 किलोमीटर से अधिक चौथी रेल लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे इस व्यस्त रेलखंड पर परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बिलासपुरङ्कनागपुर रेल खंड पर बिलासपुर से गोंदिया के बीच विभिन्न खंडों (पैचों) में चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसी क्रम में दल्लीराझराङ्करावघाट नई रेल लाइन परियोजना, जिसकी कुल लंबाई 95 किलोमीटर एवं लागत ?16,275.56 करोड़ है, के अंतर्गत 77.35 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। यह परियोजना विशेष रूप से दुर्गम एवं आदिवासी क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरसियाङ्कनया रायपुरङ्कपरमालकसा नई रेल लाइन परियोजना भी प्रगति पर है, जिसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत ?7,854 करोड़ है। यह परियोजना राज्य की राजधानी क्षेत्र सहित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त सरदेगाङ्कभालूमाड़ा नई रेल लाइन परियोजना, जिसकी लंबाई 37.24 किलोमीटर एवं लागत ?1,282 करोड़ है, क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने के साथ-साथ खनिज परिवहन को अधिक सुगम बनाएगी। वहीं रावघाटङ्कजगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना, जिसकी कुल लंबाई 140 किलोमीटर तथा लागत ?3,513 करोड़ है, बस्तर अंचल को रेल नेटवर्क से जोड़ते हुए क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। यात्री सुविधाओं के उन्नयन की दिशा में अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस की दो जोड़ी सेवाएँ तथा अमृत भारत एक्सप्रेस की एक जोड़ी सेवा संचालित की जा रही हैं, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं आधुनिक रेल यात्रा का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य में रेल नेटवर्क का निरंतर विस्तार करते हुए पिछले 10-11 वर्षों में नई रेल पटरियों का निर्माण, संपूर्ण रेल विद्युतीकरण तथा 170 फ्लाईओवर एवं अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे रेल एवं सड़क यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम हुआ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 1,083 रेलवे कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से 845 कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। ये सभी प्रयास छत्तीसगढ़ को एक आधुनिक, सुरक्षित एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित रेल नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

यात्रियों से भरी बस 200 मीटर गहरी खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत, 45 घायल...

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के बैताडी जिले में गुरुवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया।

शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे लोगों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, यह हादसा रात करीब 8 बजे हुआ। बस बैताडी जिले के पुरचौड़ी नगरपालिका क्षेत्र से आ रही थी, तभी पहाड़ी सड़क पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पहाड़ी रास्ता संकरा और खतरनाक होने के कारण बचाव कार्य में भी दिक्कत आई। यह दुर्घटना पश्चिमी नेपाल के पुरचौड़ी-7 क्षेत्र के बडगाऊ इलाके में हुई। मृतकों में सात पुरुष और एक महिला शामिल हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। घायल यात्रियों को आसपास के स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अभी हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

अगर जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आई तो कैसे होंगे भारत के साथ संबंध? शफीकुर रहमान बोले- रंगीन

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख डॉ. शफीकुर रहमान का भारत के

साथ संबंधों पर दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल, एक पत्रकार ने सवाल किया कि अगर जमात सत्ता में आती है तो बांग्लादेश के भारत के साथ किस तरह के संबंध होंगे? इसके जवाब में जमात प्रमुख हरे, चमकते हुए लाइट्स की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जब भारत के साथ संबंधों की बात आती है तो क्या आप देख सकते हैं कि यह कितना रंगीन है। इतना कहकर वह हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। हालांकि, यह टिप्पणी रहस्यमयी है। इसे जमात के अंदर इस बात का एहसास माना जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी रुख बांग्लादेश के हित में काम नहीं आए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद भारत के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। इस बीच रहमान की यह टिप्पणी शायद पहला संकेत है कि जमात भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाने को तैयार है। हालांकि, जमात ने हसीना को वहां रहने देने के लिए अक्सर भारत को निशाना बनाया है और जमात के कई हमदर्दों ने अक्सर भारत के उत्तर-पूर्व को निशाना बनाने की बात कही है। लेकिन हाल के दिनों में जमात की टॉप लीडरशिप ने अपनी बयानबाजी थोड़ी कम कर दी है। शफीकुर रहमान ने पहले दावा किया था कि दिसंबर 2025 में एक भारतीय डिप्लोमैट उनसे मिला था। चुनावी घोषणा पत्र में संबंध सुधारने पर जोर आने वाले चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधार पर भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड सहित पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों का आह्वान किया है। जमात एक पाकिस्तान समर्थक, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। अतीत में यह पार्टी अपने भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती रही है और इसके कई नेताओं या सहयोगियों ने भारत विरोधी बयान दिए हैं। हालांकि, जमात ने हाल के दिनों में हिंदुओं के साथ मेलजोल बढ़ाकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश की है।

सिंगापुर है दुनिया का सबसे जिम्मेदार देश, जानें भारत किस नंबर पर

सिंगापुर , एजेंसी। दुनिया में किसी देश की अहमियत सिर्फ उसकी आर्थिक ताकत या सैन्य शक्ति से तय नहीं होती- अब जिम्मेदारी भी एक नया पैमाना बन रही है। इसी सोच को आधार बनाकर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने रिस्पोंसिबल नेशन इंडेक्स 2026 जारी किया है, जो देशों को देखने का नजरिया ही बदल देता है।

इस इंडेक्स में यह नहीं पूछा गया कि कौन-सा देश कितना ताकतवर है, बल्कि यह परखा गया कि कौन-सा देश अपने नागरिकों, पर्यावरण और वैश्विक समुदाय के प्रति कितना संवेदनशील और उत्तरदायी है। ऐसे दौर में जब दुनिया युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु संकट से जूझ रही है, यह रिपोर्ट उन देशों को सामने लाती है जो संतुलन, नैतिकता और दीर्घकालिक सोच को प्राथमिकता देते हैं।

क्या है रिस्पोंसिबल नेशन इंडेक्स रिस्पोंसिबल नेशन इंडेक्स एक वैश्विक मूल्यांकन प्रणाली है, जिसमें 154 देशों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। इसकी खास बात यह है कि यह पारंपरिक रैंकिंग से हटकर चार व्यापक कसौटियों पर देशों को आंकता है-शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और नैतिकता नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर पर्यावरण संरक्षण के ठोस प्रयास का दबदबा देखने को मिला है। टॉप-10 देशों की सूची इस प्रकार है- सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क,

अंतरराष्ट्रीय मंच पर जिम्मेदार व्यवहार इस इंडेक्स में तष्ठक् हथियारों की संख्या या वैश्विक दबदबे को नहीं, बल्कि जिम्मेदार नेतृत्व को प्राथमिकता दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया से सिंगापुर ने दुनिया के सबसे जिम्मेदार देश के रूप में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद यूरोप के कई देशों साइप्रस, स्वीडन, चेकिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और जॉर्जिया।

भारत ने इस रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 154 देशों में 16वां स्थान हासिल किया है। भारत का स्कोर 0.5515 रहा, जो स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय पहलों और जनहित आधारित नीतियों में हुई प्रगति को दर्शाता है। खास बात यह है कि भारत इस सूची में अमेरिका और चीन जैसे बड़े और प्रभावशाली देशों से आगे रहा। वहीं पाकिस्तान को 90वां और रूस को 96वां स्थान मिला है। 2026 का सबसे बड़ा संदेश साफ है- देशों की असली पहचान उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी तय करती है। जो राष्ट्र अपने लोगों की भलाई, प्रकृति की रक्षा और वैश्विक शांति को प्राथमिकता देते हैं, वही आने वाले समय में टिकाऊ विकास का मॉडल बन सकते हैं।

बलूचिस्तान के खजाने पर ट्रंप-शहबाज की नजर!

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोने और तांबे के माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1.3 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। पाकिस्तान-ईरान सीमा के पास स्थित रेको डिक प्रोजेक्ट कुल 7 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है और उम्मीद है कि 2028 के अंत तक इसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट कनाडाई माइनर बैरिक माइनिंग कॉर्प द्वारा पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में

यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक के जरिए अमेरिकी निवेश किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बैरिक की है, जबकि बाकी 25 प्रतिशत तीन फेडरल सरकारी कंपनियों की है और 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बलूचिस्तान सरकार की है। बलूचिस्तान में अलगाववादियों और जिहादियों के लगातार हमले होते रहते हैं, जिससे खदान के लिए सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। इस प्रोजेक्ट के लिए तांबे के कंसंट्रेट को कराची तक ले जाने और फिर विदेश में प्रोसेसिंग के लिए रेलवे लाइन को अपग्रेड करने की भी जरूरत है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक सहित अन्य लेंडर्स मिलकर 2.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फाइनेंसिंग पैकेज तैयार कर रहे हैं। रेको डिक पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। इस्लामाबाद इस खदान पर अपनी मिनरल रणनीति को मजबूत करने के लिए निर्भर है, जबकि कनाडाई माइनर अपने सबसे बड़े लॉन्ग-टर्म प्रोजेक्ट्स में से एक को आगे बढ़ा रहा है। शहबाज शरीफ सरकार ने इस कदम का स्वागत किया और इसे देश के माइनिंग सेक्टर और आर्थिक सुधारों पर भरोसे का वोट बताया। इस्लामाबाद को उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट अपने पूरे समय में अरबों डॉलर का रेवेन्यू देगा और पैसे की कमी से जूझ रहे देश के विकास में अहम योगदान देगा।

बिल गेट्स से एलन मस्क तक: दुनिया के दिग्गज हस्तियों के नाम एपस्टीन फाइल में आने से भूचाल

वाशिंगटन, एजेंसी। यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों से जुड़ी एपस्टीन फाइल्स एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बन गई हैं। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एपस्टीन फाइल से जुड़े लाखों पन्नों के दस्तावेज जारी किए गए हैं। जिसमें दुनियाभर के कई ऐसे दिग्गजों के एपस्टीन के साथ संबंध का खुलासा हुआ है कि गूगल ट्रेंड्स पर इस मामले की सर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दरअसल, एपस्टीन फाइल के नए दस्तावेजों में दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्तियों- जिनमें एलन मस्क, बिल गेट्स और

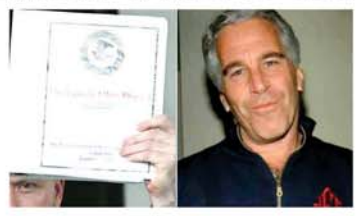

डोनल्ड ट्रंप के साथ एपस्टीन के कथित संबंधों का विवरण दिया गया है। लाखों पन्नों और हजारों तस्वीरों में आए दुनिया के प्रमुख हस्तियों के नाम ने वैश्विक राजनीति और कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। ज्ञात हो कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा 30 जननरी को एपस्टीन फाइल से जुड़े नए दस्तावेज जारी किए गए। लाखों पन्नों के इस फाइल में 180,000 चित्र, 2,000 वीडियो है। जिसमें रिचर्ड ब्रैनसन, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे कई जाने-माने हस्तियों के यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ संबंध उजागर हुए हैं। हालांकि, इन फाइलों में नाम होने का अर्थ सीधे तौर पर किसी अपराध की पुष्टि नहीं है। पहले जारी किए गए दस्तावेजों में जिन लोगों के नाम आए हैं, उनमें से कई लोगों ने एपस्टीन से संबंधित किसी भी गलत काम से इनकार किया है। एपस्टीन फाइल में अरबति एलन मस्क और जेफरी के बीच बातचीत का ईमेल शामिल है।

अरबों का गुपचुप कारोबार! चीन में धड़ल्ले से बिक रहे कंडोम

बीजिंग, एजेंसी। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो अक्सर हमारा ध्यान कड़े कानूनों या सरकारी नीतियों पर जाता है लेकिन इन सबके बीच एक छोटा सा प्रोडक्ट खामोशी से दुनिया की आबादी को संतुलित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। हम बात कर रहे हैं कंडोम की। जिस प्रोडक्ट का नाम सुनते ही अक्सर लोग झिझक जाते हैं आज उसका बाजार एशिया में अरबों डॉलर तक पहुंच चुका है। आइए जानते हैं कि एशिया के किस देश में इसका सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा हो चुका है। कंडोम की खपत में एशिया का सुपरपावर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय शोध और व्यापारिक रिपोर्टों के अनुसार एशिया में कंडोम की बिक्री के मामले में चीन निर्विवाद रूप से नंबर-1 पर है। चीन में हर साल लगभग 5.8 अरब (कंडोम यूनिट्स बेची जाती हैं। यह संख्या पूरे एशिया की कुल खपत का एक बड़ा हिस्सा है। इस सूची में भारत दूसरे स्थान पर है जबकि तुर्की तीसरे नंबर पर आता है। हालांकि चीन और भारत के बीच का अंतर अभी भी काफी ज्यादा है।

अरबों डॉलर का कारोबार: 2030 तक होगा दोगुना: चीन का कंडोम बाजार सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि निवेश का एक बड़ा केंद्र बन गया है:

मार्केट वैल्यू: साल 2023 में चीन का कंडोम बाजार करीब 3.69 बिलियन डॉलर (लगभग 30,000 करोड़ रुपये) का था।

भविष्य का अनुमान: विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक यह बाजार बढ़कर 7.24 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।

ग्रोथ रेट: यह सेक्टर हर साल 10त्न की रफ्तार से बढ़ रहा है जो किसी भी अन्य एफएमसीजी प्रोडक्ट के मुकाबले काफी बेहतर है।

चीन में कंडोम की इतनी ज्यादा बिक्री के पीछे तीन मुख्य कारण हैं: विशाल आबादी: चीन की 1.4 अरब की आबादी में से लगभग 60 करोड़ लोग यौन रूप से सक्रिय श्रेणी में आते हैं। चीन सरकार ने यौन स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव के लिए इसे एक अनिवार्य स्वास्थ्य उत्पाद के रूप में प्रचारित किया है। बेहतर यौन शिक्षा और आधुनिक जीवनशैली के कारण अब वहां कंडोम खरीदने को लेकर सामाजिक शर्मिंदगी कम हो गई है।

ब्रांड्स और क्वालिटी का बोलबाला चीन के बाजार में 85त्न से ज्यादा हिस्सा लेटेक्स कंडोम का है। वहां की जनता ओकामोटो सागामी और इलासुन जैसे ब्रांड्स पर भरोसा करती है। दिलचस्प बात यह है कि चीन अपनी खपत पूरी करने के लिए थाईलैंड, जापान और मलेशिया जैसे देशों से भारी मात्रा में कंडोम आयात भी करता है।

भारत के लिए क्या है सबक?

भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार तो है लेकिन यहां आज भी ग्रामीण इलाकों में इसे खरीदने को लेकर भारी सामाजिक झिझक देखी जाती है। हालांकि सरकारी योजनाओं और सुरक्षित संबंधों के प्रचार की वजह से भारत का बाजार भी अब तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है।

सऊदी से ओमान तक... वो 6 खाड़ी देश जिनके साथ भारत जल्द ही पक्का कर सकता है फ्री ट्रेड पैक्ट

अबुधावी, एजेंसी। भारत और मिडिल ईस्ट देशों के छह देशों के ग्रुप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने गुरुवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए।

टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक प्रस्तावित ट्रेड पैक्ट के दायरे और तरीकों की रूपरेखा बताते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में ये हस्ताक्षर किए गए। जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के छह देशों का एक यूनियन है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उन्होंने बताया, ये दोनों ट्रेडिंग पार्टनर 5,000 से ज्यादा सालों से एक-दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 10 मिलियन भारतीय जीसीसी क्षेत्र में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। गोयल ने कहा, यह बहुत सही है कि अब हम एक ज्यादा मजबूत और ठोस ट्रेडिंग एग्रीमेंट करें, जिससे सामान और

सेवाओं का ज्यादा मुक्त प्रवाह हो सके, नीति में अनुमान और स्थिरता आए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि यह समझौता जीसीसी देशों के साथ-साथ भारत की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा। जहां भारत दुनिया में अनाज का एक बड़ा उत्पादक है, वहीं जीसीसी देश तेल और गैस के निर्यातक हैं। गोयल ने कहा, हमें भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और जीसीसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ बढ़ाने के लिए भी मौका मिलेगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने वाली हाई-क्वालिटी कंपनियों का साथ भी मिलेगा। इस पार्टनरशिप से हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारत की इन्फॉर्मेशन और कम्युनिके शन टेक्नोलॉजी कंपनियों को लगातार बढ़ते जीसीसी मार्केट में मौके मिलेंगे। भारत ने मई 2022 में पहले ही यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड पैक्ट लागू कर दिया है। गोयल ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में 38 विकसित देशों के साथ नौ ट्रेड पैक्ट फाइनल किए हैं।

भारत पर कम टैरिफ से घबराया बांग्लादेश, अब ट्रंप के साथ यूनुस करने जा रहे सीक्रेट डील

ढाका, एजेंसी। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद बांग्लादेश घबरा गया है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका और बांग्लादेश 9 फरवरी को एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। इस डील की शर्तों को लेकर गोपनीयता के कारण इसकी काफी आलोचना हो रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले इस सीक्रेट डील की चर्चा हो रही है। भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के बाद बांग्लादेश ने डील को फाइनल करने की जल्दी की है। ट्रंप ने भारतीय सामान पर टैरिफ घटाकर 18 परसेंट कर दिया गया है। बांग्लादेश को डर है कि अगर वह उतने ही कॉम्पिटिटिव या बेहतर शर्तें हासिल नहीं कर पाता है तो वह भारत से मार्केट शेयर खो देगा। उसकी इकॉनमी बहुत ज्यादा अमेरिका को रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। यह उसके अमेरिकी एक्सपोर्ट का लगभग 90 परसेंट है। यह डील अप्रैल 2025 में वाशिंगटन द्वारा ढाका पर 37 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाने के बाद हुई है। जुलाई में टैरिफ पर बातचीत करके इसे 35 प्रतिशत और फिर अगस्त में आखिरकार 20 प्रतिशत कर दिया गया। आने वाले ट्रेड डील से टैरिफ को और कम करके 15 प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, 2025 के बीच में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ एक औपचारिक नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसमें सभी टैरिफ और व्यापार बातचीत को गोपनीय रखने का वादा किया गया था। इस एग्रीमेंट का कोई भी ड्राफ्ट न तो जनता, न संसद और न ही प्रमुख इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ शेयर किया गया है। इस डील में कई शर्तें हैं। पहली, चीन से इंपोर्ट कम करना और चीन के बजाय अमेरिका से मिलिट्री इंपोर्ट बढ़ाना। दूसरी, अमेरिकी इंपोर्ट बांग्लादेश में बिना किसी रोक-टोक के आ सकें और दक्षिण एशियाई देश को बिना कोई सवाल उठाए अमेरिकी स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन को मानना होगा।

बलूचिस्तान में पाक सेना का बड़ा ऑपरेशन: 216 आतंकवादी ढेर

पेशावर, एजेंसी। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हुए आतंकी हमलों के जवाब में कई दिनों तक चले अभियान में कम से कम 216 आतंकवादी, 36 नागरिक और 22 जवान मारे गए हैं। सेना ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में कहा कि उसने 26 जनवरी को शुरू किया गया अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि विश्वसनीय और खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद पंजगुर और हरनाई जिले के बाहरी इलाकों में अभियान शुरू किए गए। इसने बताया कि कई दिन चले अभियान में 216 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आईएसपीआर ने बताया कि अभियान के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित 36 आम नागरिक तथा सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 22 कर्मी मारे गए। भारत ने बलूचिस्तान में शांति भंग करने की कोशिशों में उसकी संलिप्तता के पाकिस्तान के आरोपों को लगातार सिरे से खारिज किया है और कहा है कि यह इस्लामाबाद की अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की रणनीति का हिस्सा है।

वापस धरती पर लौटेगा इंटरेशनल स्पेस स्टेशन

वाशिंगटन, एजेंसी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन साल 2030 में जब पृथ्वी पर लौटेगा, तब यह सिर्फ एक अंतरिक्ष स्टेशन का अंत नहीं होगा, बल्कि करीब 30 साल तक चले वैश्विक सहयोग और शांति का एक बड़ा अध्याय भी खत्म हो जाएगा। यह वह दौर था जब अंतरिक्ष मानव सहयोग का सबसे मजबूत उदाहरण बना।

नवंबर 2000 से अब तक आईएसएस में लगातार इंसानों की मौजूदगी रही है। फुटबॉल मैदान जितना बड़ा यह स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर करीब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमते हुए विज्ञान, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को आगे बढ़ाता रहा है।

आईएसएस अब तक का सबसे बड़ा मानव-निवास योग्य अंतरिक्ष प्रयोगशाला रहा है। यहां वैज्ञानिक प्रयोग, नई तकनीकों का

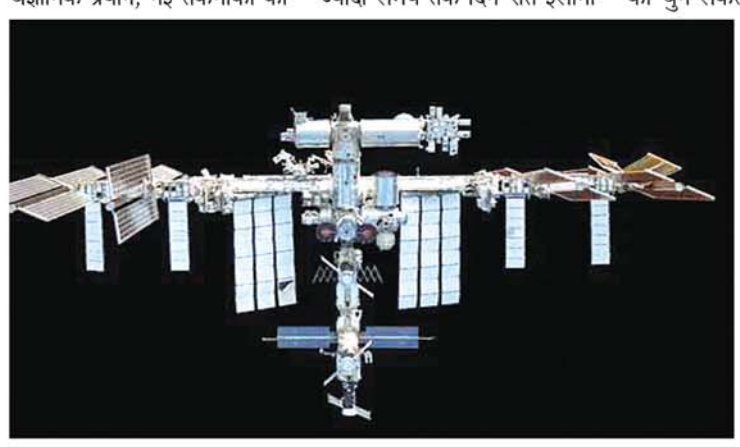

परीक्षण और अंतरिक्ष में रहने की मानवीय क्षमता को समझा गया। नासा के पूर्व अधिकारी जॉन हॉर्नयाक के अनुसार, 25 साल से ज्यादा समय तक दिन-रात इंसानों का अंतरिक्ष में रहना मानव इतिहास की एक असाधारण उपलब्धि है। यह दिखाता है कि इंसान टकराव की बजाय सहयोग को चुन सकता है।

आईएसएस की योजना अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के बाद बने नए सहयोग की भावना से शुरू हुई थी। पुराने प्रतिद्वंद्वी देशों ने मिलकर इस स्टेशन को बनाया। यह बात खास मानी जाती है कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस और पश्चिमी देशों के रिश्तों में तनाव के बावजूद, आईएसएस पर सहयोग अब तक बना रहा।

फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस के अधिकारी लियोनेल सुशे ने कहा कि मानव अंतरिक्ष उड़ान इतिहास की सबसे अहम अंतरिक्ष दौड़ रही है और आईएसएस इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण था।

समय के साथ आईएसएस के कई हिस्से पुराने हो चुके हैं और उनकी उम्र पूरी होने वाली है। इसी वजह से नासा ने एलन मस्क की कंपनी को एक खास वाहन बनाने की जिम्मेदारी दी है, जो 2030 में आईएसएस को सुरक्षित तरीके से पृथ्वी के वातावरण में वापस लाएगा।

जॉन हॉर्नयाक के मुताबिक, स्टेशन की रफ्तार कम की जाएगी और इसे प्रशांत महासागर के एक निर्जन इलाके में गिराया जाएगा, ताकि किसी इंसान या जमीन को नुकसान न पहुंचे। इस इलाके को पहले भी स्पेस स्टेशन जैसे कई अंतरिक्ष यानों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसे पॉइंटनीमो कहा जाता है।

2030 के बाद अंतरिक्ष की तस्वीर

आईएसएस के खत्म होने के बाद लो अर्थ ऑर्बिट में सिर्फ चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन ही बचा रहेगा। अब अमेरिका का ध्यान निजी कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले स्पेस स्टेशनों पर ज्यादा है। भविष्य में अंतरिक्ष एजेंसियों को अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए निजी कंपनियों को शुल्क देना होगा।

यूएस को 29 रन से हराया; कप्तान सूर्या की फिफ्टी, सिराज को 3 विकेट

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत

मुंबई। भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत की है। टीम ने शनिवार के आखिरी मैच में को 29 रन से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने टॉस हारकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 162 रन बनाए। टीम इंडिया के शुरुआती 4 विकेट महज 46 रन पर गिर गए थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 49 बॉल पर 84 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 162 रन का टारगेट चेज करते हुए ू की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। शुभम रंजने और संजय कृष्णमूर्ति ने 37-37 रन बनाए। जबकि मिलिंद कुमार ने 34 रन स्कोर किए। भारत से मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए।

भारत ने अमेरिका को 29 रन से हराया

टी 20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने अमेरिका को 29 रन से हराया। अमेरिका ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 132 रन बनाए। मैच की आखिरी गेंद पर सिराज ने शुभम रंजने को यॉर्कर पर LBW आउट किया। सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जीत के करीब भारत 19वें ओवर में हार्दिक ने 10 रन दिए। ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ पर छक्का जड़ा। आखिरी ओवर में जीत के लिए 41 रनों की जरुरत है। यूएस का 7वां विकेट गिरा, मोहसिन आउट 18वें ओवर की चौथी बॉल पर ने 7वां विकेट गंवाया। अर्शदीप सिंह ने मोहम्मद मोहसिन को 8 रन के स्कोर पर आउट किया। डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा ने कैच पकड़ा। अर्शदीप सिंह को दूसरा विकेट मिला।

भारत का विजयी आगाज, अमेरिका को 29 रन से हराया

टी20 विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है। भारत अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ मुकाबले से करेगा। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रंगारंगा उद्घाटन समारोह का प्रबंध किया। पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह मैदान पर ट्रॉफी लेकर पहुंचे। टॉस अमेरिका ने जीता और भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी चुनी।

ब्रीफ न्यूज

न्यूज़ीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से अधिक बड़ा खिताबी दावेदार मानते हैं अश्विन

चेन्नई। दिग्गज स्पिनर आर अश्विन के अनुसार इस बार टी20 विश्वकप क्रिकेट न्यूजीलैंड टीम जीत सकती है। अश्विन का ये दावा हैरान भरा है क्योंकि हाल में भारतीय टीम ने पांच टी20 मैच में कीवी टीम को 4-1 से हराया था। वहीं अश्विन का मानना है कि न्यूजीलैंड को भारत में भले ही हार का सामना करना पड़ा था पर उसे उसमें काफी कुछ सीखने को भी मिला। ऐसे में वह जीत की ऑस्ट्रेलिया से अधिक बड़ी दावेदार है। वह इस बड़े टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीतने के लिए पूरा अनुभव लगा देगी। उसे भारत में खेलने भी लाभ मिलेगा।भारत के खिलाफ सीरीज में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। एडम मिल्ने और माइकल ब्रेसवेल की के फिट नहीं होने और कई बल्लेबाजों की खराब फॉर्म के कारण भी उसे नुकसान हो सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के बाद टूर्नामेंट में उतर रही है। ऐसे में उसका मनोबल गिरा हुआ है। इसके अलावा मिचेल स्टार्क के संन्यास और पैट कमिंस के नहीं होने से भी उसे नुकसान होगा।

फेरर को एकदशक पहले ही अंदाजा हो गया था अल्काराज़ बनाएंगे रिकार्ड

मैड्रिड । ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले कार्लोस अल्काराज़ अभी टेनिस जगत में सबसे कम उम्र में चारों ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी है। वहीं स्पेन के डेविस कप कप्तान और पूर्व टॉप-10 खिलाड़ी डेविड फेरर का कहना है कि उन्होंने एक दशक पहले ही अल्काराज की प्रतिभा देख ली थी और उन्हें अंदाज हो गया था कि वह नये रिकार्ड बनाऐंगे। फेरर ने अल्काराज़ के साथ 2014 में हुई एक ऐसी ट्रेनिंग सत्र की बातों को याद करते हुए कहा कि तब अल्काराज़ की उम्र महज़ 14 साल थी, जबकि फेरर उस समय शीर्ष पर थे। यह ट्रेनिंग सेशन पूर्व विश्व नंबर-1 जुआन कार्लोस फेररो के कहने पर आयोजित किय गया था। फेरर शुरू में ज्यादा उत्साहित नहीं थे और उन्होंने साफ कहा था कि प्री-सीजन ट्रेनिंग में वे समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं पर जब उन्होंने अल्काराज़ को खेलते हुए देखा तो उनकी सोच पूरी तरह बदल गयी। उन्होंने बताया कि आमतौर पर पेशेवर खिलाड़ियों के सामने युवा खिलाड़ी टिक नहीं पाते पर अल्काराज़ ने हर शॉट संभाला बल्कि तीसरे ही रिटर्न पर गेंद की रफ्तार बढ़ाकर उन्हें हैरान कर दिया। उस पल फेरर को उनमें वहीं छवि दिखी जो उन्होंने है, राफेल नडाल में दिखी थी। गौरतलब है कि दोनों के बीच एक सुपर टाईब्रेक भी खेला गया, जिसमें फेरर ने 10-8 से जीत हासिल की।

टी-20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में हारते-हारते जीता पाकिस्तान

फहीम ने आखिरी 2 ओवर में 3 छक्के लगाकर मैच पलटा, नीदरलैंड 3 विकेट से हारा

कोलंबो। 2009 का चैंपियन पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में नीदरलैंड से हारते-हारते जीत गया। टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 29 रन बनाने थे। उसे फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के लगाकर 3 विकेट की जीत दिलाई। 18वें ओवर तक नीदरलैंड का पलड़ा भारी था। 19वें ओवर की पहली बॉल पर फहीम ने छक्का लगाया, लेकिन दूसरी बॉल पर मैक्स ओडाउड से उनका कैच ड्रॉप हो गया। जीवनदान मिलने के बाद फहीम ने दो छक्के लगाकर मैच का रुख पाकिस्तान की ओर कर दिया। उन्होंने 11 बॉल पर नाबाद 29 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोलंबो में शनिवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान की के ओपनर साहिबजादा फरहान ने 47 रन बनाए। सईम अयूब ने 24 रन बनाए। नीदरलैंड की ओर पॉल वैन मीकेरेन और आर्यन दत्त को 2-2 विकेट मिले। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बैटिंग कर रही नीदरलैंड की पूरी टीम 19.5 ओवर में 147 रन पर वे 3 रन से फिफ्टी चूक गए।

शादाब खान भी पवेलियन लौटे

17वें ओवर की पहली बॉल पर पाकिस्तान ने 7वां विकेट गंवाया। उन्होंने शादाब खान (8 रन) को लोगन वैन बीक ने विकेटकीपर स्कॉट एडवर्ड्स के हाथों कैच कराया।सिमट गई। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सलमान मिर्जा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। नीदरलैंड के 10 में से 9 बल्लेबाज कैच आउट हुए, जबकि केवल एक विकेट अबरार अहमद ने कॉलिन एकरमैन को बोल्ड कर हासिल किया। मैच का पाकिस्तान का छठा विकेट गिरा, हसन नवाज आउट 16वें ओवर की पहली बॉल पर पाकिस्तान ने हसन नवाज (6 रन) का विकेट गंवाया। उन्हें कॉलिन एकरमैन ने विकेटकीपर स्कॉट एडवर्ड्स के हाथों कैच कराया।

फहीम ने पाकिस्तान को जिताया, 3 छक्के मारे

पाकिस्तान ने 148 रन का टारगेट 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर चेज कर लिया। फहीम अशरफ ने चौका मारकर जीत दिलाई। उन्होंने 19वें ओवर में 3 छक्के भी मारे। इस ओवर में फहीम का कैच ड्रॉप भी हुआ।

बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 : भारत के 12 मुक्केबाज़ फाइनल में

सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना भारत

ला नुसिया। स्पेन के ला नुसिया में आयोजित बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 में भारतीय मुक्केबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट के आखिरी दिन 12 फाइनल स्थान अपने नाम किए। इनमें आठ महिलाएँ और चार पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने अलग-अलग वेट कैटेगरी में प्रभावशाली जीत दर्ज की और भारत को मेडल टेबल पर शीर्ष दावेदार में ला खड़ा किया। पुरुष वर्ग में सचिन (60 किग्रा) ने इंग्लैंड के जैक ड्राइडन को हराकर लगातार दूसरी बड़ी जीत हासिल की। उनके बेहतरीन फॉर्म ने भारत को मजबूत शुरुआत दी। वहीं महिलाओं में ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा) ने वेल्स की रोज़ी एक्लेस के खिलाफ सर्वसम्मत निर्णय से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई।

20 देशों के 200 से अधिक बॉक्सरों की भागीदारी वाले इस इवेंट में शनिवार के फाइनल में भारत 12 खिलाड़ियों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। इस मामले में भारत कजाकिस्तान (11), यूक्रेन (5) और मेजबान स्पेन (4) से आगे है। भारत ने कम से कम एक गोल्ड मेडल पक्का कर लिया है, क्योंकि महिला 54 किग्रा वर्ग का फाइनल पूरी तरह भारतीय मुक्केबाज़ों प्रीति और पूनम के बीच खेला जाएगा।

महिला वर्ग में भारत का दबदबा पूरे सेशन में देखने को मिला। मंजू रानी (48 किग्रा), नीतू (51 किग्रा), प्रिया (60 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा) और नैना (80 किग्रा) सभी ने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर शीर्ष मुकाबले में प्रवेश किया। यह प्रदर्शन महिला मुक्केबाज़ी में भारत की गहराई और निरंतरता का संकेत है। वहीं पुरुषों में दीपक (70 किग्रा), आकाश (75 किग्रा) और अंकुश (80 किग्रा) ने भी फाइनल में प्रवेश किया। दीपक ने कजाकिस्तान के नुरबेक मुरसल को पहले ही राउंड में आरएससी से हराकर दिन का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया। आकाश और अंकुश ने कठिन कजाख प्रतिद्वंद्वियों को मात देकर स्वर्ण मुकाबले में जगह बनाई।

ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज की

सागर धनकड़ हत्याकांड

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनकड़ की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें सुशील कुमार ने नियमित जमानत की मांग की थी। सुशील कुमार और अन्य आरोपियों पर आरोप है कि मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद के चलते उन्होंने सागर धनकड़ और उनके साथियों पर जानलेवा हमला किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि धनकड़ को किसी भारी वस्तु से सिर में गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिसके कारण उनकी मौत हुई। इस घटना में धनकड़ के दो दोस्त भी घायल हुए थे। घटना के तुरंत बाद सुशील कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले अदालत ने 19 जुलाई 2023 को उनकी घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। लेकिन नियमित जमानत को लेकर उनकी पिछली अर्जी और अब दायर ताजा अर्जी दोनों को अदालत ने निरस्त कर दिया। अक्टूबर 2022 में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की हत्या, आपराधिक साजिश, धमकी और घातक हथियारों से दंगा करने जैसी गंभीर धाराओं में सुशील कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके अतिरिक्त, उनके विरुद्ध हथियार अधिनियम के तहत भी कार्रवाई तय की गई है। अदालत ने माना था कि धनकड़ को कथित रूप से अगवा कर स्टेडियम लाया गया और वहां कई आरोपियों ने बेसबॉल व हॉकी स्टिक से उन पर हमला किया। अदालत का यह फैसला सुशील कुमार के लिए कानूनी मोर्चे पर एक और बड़ा झटका माना जा रहा है।

रोनाल्डो फिर बदल सकते हैं क्लब

लिस्बन । पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। विश्व के बेहतरीन स्ट्राइकर रोनाल्डो आजकल सऊदी अरब के क्लब अल नास्र में हैं पर कहा जा रहा है कि वह संतुष्ट नहीं हैं और किसी अन्य क्लब में जा सकते हैं। रोनाल्डो फुटबॉल जगत के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं। ऐसे में उनको शामिल करने की दौड़ में कई क्लब आ जाएंगे। हैं। अपने करियर में वह मैनचेस्टर यूनाइटेड से लेकर रियल मैड्रिड और जुवेंटस तक छाये रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में अल नास्र से रोनाल्डो के खुश नहीं होने से उनके किसी अन्य क्लब में जाने की अटकलें लगायी जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मोरक्को के क्लब वीदाद कासाब्लांका की नजरें उनपर हैं। वीदाद अफ्रीकी फुटबॉल में बड़ा नाम है और नियमित रूप से सीएएफ चैंपियंस लीग खेलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्लब ने पहले भी रोनाल्डो को शामिल करने को लेकर रुचि दिखाई थी, जिससे अफ्रीकी फुटबॉल में उनके खेलने की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। इसके अलावा रियल मैड्रिड में वापसी की अटकलें भी हैं। रोनाल्डो ने इस क्लब के लिए नौ वर्षों में चार चैंपियंस लीग खिताब जीते थे। मौजूदा समय में टीम प्रबंधन और चोटों से जूझ रही मैड्रिड उनके जैसे अनुभवी खिलाड़ी को लेना चाहेगी। इसके अलावा अमेरिका की मेजर लीग सॉकर की दिग्गज टीम लॉस एंजेलिस गैलेक्सी भी उन्हें शामिल करना चाहती है। माना जा रहा है कि अमेरिका में खेलना रोनाल्डो को प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ ब्रांड विस्तार का बड़ा मंच दे सकता है, खासकर तब जब लियोनेल मेसी पहले ही वहां खेल रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस का पेरिस सेंट-जर्मेन भी चर्चा में है। स्टार खिलाड़ियों से भरी इस टीम में रोनाल्डो का जुड़ना चैंपियंस लीग के लिए अनुभव और मानसिक मजबूती ला सकता है। वहीं, स्पोर्टिंग सीपी में वापसी उनके करियर को भावनात्मक पूर्णता दे सकती है, जहां से उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल की शुरुआत की थी।

स्पेन के वालेंसिया में जर्मनी और बेल्जियम के बीच एफआईएच हॉकी प्रो लीग महिला मैच के दौरान बेल्जियम के खिलाड़ी गोल का जश्न मनाते हुए।

शिमरोन हेटमायर ने 64 रनों की पारी खेली

वेस्टइंडीज:स्कॉटलैंड को 35 रन से हराया

कोलकाता। वेस्टइंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने टी-20 वर्ल्ड कप के पहले ही दिन हैट्रिक ले ली है। उनकी दमदार गेंदबाजी से वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रनों के अंतर से हरा दिया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में टॉस हारकर बैटिंग कर रही वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 182 रन बनाए। 183 रन का टारगेट चेज कर रही स्कॉटलेंड 18.5 ओवर में 147 रन पर ऑलआउट हो गई। इससे पहले शिमरोन हेटमायर ने 36 बॉल पर 64 रन बनाए। ओपनर ब्रैंडन किंग ने 35 रन का योगदान दिया। रोवमैन पॉवेल और शेरफेन रदरफोर्ड ने 24 रन बनाए। जेसन होल्डर ने 2 विकेट लिए। होल्डर को दूसरा विकेट, विंडीज 35 रन से जीता 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर जेसन होल्डर ने मार्क वाट को पॉवेल के हाथों कैच कराया। इसी के साथ स्कॉटलैंड की टीम 147 रन पर ऑलआउट हो गई। वेस्टइंडीज ने इस मैच को 35 रन से जीता लिया है। शेफर्ड ने ओवर में दो विकेट झटके बैरिंगटन और ब्रूस में फिफ्टी पार्टनरशिप, स्कॉटलैंड 100 पार कप्तान रिची बैरिंगटन और टॉम ब्रूस ने फिफ्टी पार्टनरशिप करके स्कॉटलैंड को संभाल लिया। दोनों ने रोमारियो शेफर्ड के ओवर की पहली बॉल पर 2 रन लेकर फिफ्टी पार्टनरशिप की। टीम ने पावरप्ले के अंदर 3 विकेट गंवा दिए थे।

शेफर्ड ने हैट्रिक सहित 5 विकेट झटके

उन्होंने 17वें ओवर में माइकल लीस्क (जीरो), मैथ्यू क्रॉस (11 रन), ओलिवर डैविडसन (जीरो) को आउट करके हैट्रिक पूरी की। फिर छठी बॉल पर साफयान शरीफ (जीरो) को भी आउट कर दिया। उन्हें पावरप्ले में ब्रैंडन मैक्मुलेन (14 रन) का विकेट भी मिला।

पटवारी-मैनेजर की मनमानी से टूटी किसानों की उम्मीदें, भौतिक सत्यापन के बाद भी धान बेचने से वंचित रहे दर्जनों किसान

बकावंड/बस्तर/मूक पत्रिका

(पवन कुमार नाग) -धान खरीदी व्यवस्था में अव्यवस्था और अधिकारियों की मनमानी से किसान बुरी तरह परेशान हैं। करपावंड धान खरीदी केंद्र में भौतिक सत्यापन पूर्ण होने के बावजूद कई किसान अपना धान बेचने से वंचित रह गए, जिससे उनमें भारी रोष व्याप्त है। किसानों का आरोप है कि शासन के स्पष्ट आदेशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और इसका खामियाजा सीधे अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है।किसानों का कहना है कि मूसलाधार बारिश, कीट रोग और आर्थिक संकट से जूझते हुए वे दिन-रात खेतों में पसीना बहाकर फसल तैयार करते हैं। धान बेचकर ही वे शासन से लिया गया कर्ज चुकाने में सक्षम हो पाते हैं, लेकिन जब उपज बेचने का समय आता है तो उनके साथ अन्याय किया जाता है।करपावंड धान खरीदी केंद्र में रिकॉर्ड में गलत अंकन और किसानों की सहमति के बिना रकबा जांच कर गलत प्रविष्टि किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। किसानों का कहना है कि पटवारी की गलती या जानबूझकर की गई मनमानी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जिससे कई किसान अपना पूरा धान नहीं बेच पाए। बकावंड विकासखंड में धान खरीदी को लेकर भारी अव्यवस्था देखने को मिली है। किसानों ने सोसायटी मैनेजर और पटवारी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पीड़ित किसानों ने बस्तर विधायक, कलेक्टर एवं एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। किसानों का आरोप है कि भौतिक सत्यापन पूरा होने के बावजूद उनकी सहमति के बिना धान बिक्री रोकी गई। शासन द्वारा समस्या समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को दो दिन का समय दिए जाने के बाद भी जमीनी हालात जस के तस बने हुए हैं। कई किसानों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर कम मात्रा का टोकन काटा गया, जिससे वे अपना पूरा धान एकसाथ नहीं बेच सके। धान बेचने पहुंचे किसानों ने बताया कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत पंजीयन और भौतिक सत्यापन कराया था, फिर भी उन्हें परेशान किया गया।

सीमांत किसानों के लिए यह स्थिति और गंभीर हो गई है, क्योंकि उन्हें परिवहन, मजदूरी और समय का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। उनका कहना है कि 32 किसानों का भौतिक सत्यापन पूरा होने के बावजूद केवल 4 किसान ही धान बेच पाए, जबकि शेष 28 किसान वंचित रह गए।किसानों ने गलत जानकारी भेजने वाले पटवारी और कम मात्रा का टोकन काटने वाले सोसायटी मैनेजर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

नाबालिक लडकी को जंगल मे ले जाकर बेईज्जती एंव छेडछाड करने वाले को आरोपी को किया गया गिरफ्तार

इष्ट्राग्राम के माध्यम से हुई था नाबालिक लडकी की आरोपी से दोस्ती

कांकेर /मूक पत्रिका

उत्तर बस्तर कांकेर प्रार्थी के द्वारा थाना कांकेर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, आरोपी कोहिल साहू के द्वारा इसकी नाबालिक लड़की को बेईज्जती व छेडछाड करने की रिपोर्ट पर थाना कांकेर में अप.क्र. 55/2026 धारा 74, 75 (2) बीएनएस 8 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए निखिल राखेचा पुलिस अधीक्षक जिला उ.ब. कांकेर के निर्देषन में, योगेश साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर के मार्गदर्शन में एंव मोहसिन खान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर के पर्यवेक्षण में, थाना कांकेर से टीम तैयार आरोपी का पता तलाश कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का मुआयना कर नक्शा तैयार किया गया। प्रकरण के आरोपी कोहिल साहू पिता स्व. बहादुर साहू उम्र 20 वर्ष निवासी सारवंडी, नरहरपुर थाना कांकेर जिला उ.ब. कांकेर के बारे में पता किया जो आरोपी अपने सकुनत पर रहना पता चलने पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को पकड़कर थाना लाया गया। प्रकरण में आरोपी कोहिल साहू से घटना के बारे में बारिकी से पूछताछ किया गया जो आरोपी ने बताया कि, पीड़िता को नाबालिक जानते हुए बेईज्जती व छेडछाड करने की नियत से जंगल ले जाना अपराध कबूल करना स्वीकार करने से दिनांक 07.02.2026 को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। संपूर्ण कार्यवाही में भुनेश्वरी भगत, हेतेश्वरी चेलक, कौशल साहू कांकेर का सहयोग रहा है।

पी एम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल अंबागढ़ चौकी में हुआ संविदा शिक्षक भर्ती घोटाला

अम्बागढ़ चौकी/मूक पत्रिका

सूत्रों से जानकारी मिली है कि अंबागढ़ चौकी में स्थित पी एम श्री आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एक शिक्षिका को गलत दस्तावेज के आधार पर शाला में नियुक्ति दी गई है जोकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जानकारी के अनुसार दिनांक 03-08-2022 को शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए अंग्रेजी माध्यम के योग्यता धारी आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन निकाला गया था। किंतु कांग्रेस के शासनकाल में हुई इस भर्ती में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ और पैसों का लेनदेन कर योग्य आवेदकों को इस भर्ती से बाहर दिया गया और एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भर्ती हेतु हिन्दी माध्यम की शिक्षिका की भर्ती की गई है। वह पद अंग्रेजी माध्यम के लिए निकाला गया था जबकि शासन द्वारा निकाले गए आवेदन के नियम शर्तों में यह स्पष्ट लिखा गया था कि ईन पदों पर सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना है। मगर कांग्रेस शासनकाल में खुलकर नियम शर्तों की धज्जियां उड़ाई गई और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में आदिवासी अभ्यर्थियों को सारे दस्तावेज सही होने पर भी बाहर का रास्ता दिखाया गया और जो शिक्षिका हिंदी माध्यम से पढ़ी लिखी हुई है उसकी भर्ती अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया। इससे साफपता चलता है कि कांग्रेस शासनकाल में सरकार द्वारा स्वयं के शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूल में किस तरह फर्जीवाड़ा किया गया है जोकि बहुत शर्मनाक है और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में हिंदी माध्यम के शिक्षक को नियुक्त किया गया है और यह भी जानकारी मिली है कि जिस शिक्षिका की भर्ती नियमों के विरुद्ध किया गया है एक तो वह हिंदी माध्यम की है और दूसरी तरफ वह शासन द्वारा उस दिनांक को निकाले गए भर्ती नियमों में मांगे गए आयु सीमा से भी अधिक थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व कांग्रेस की सरकार में इस तरह का भ्रष्टाचार करके शिक्षा विभाग को कलंकित किया गया है और पी एम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल अंबागढ़ चौकी के बच्चों के साथ खिलवाड़ भी साथ उन आवेदकों का क्या जिनके पास सभी योग्यताएं होने के बाद भी उनका चयन नहीं किया गया और पैसों का लेनदेन कर शिक्षा का व्यावसायीकरण कर दिया। इसी कारण अंबागढ़ चौकी में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति किया जा रहा है क्योंकि फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षक स्कूल प्रशासन की कठपुतलियां बनकर काम कर रही है वें बच्चों के हित के लिए नहीं और सिर्फ स्कूल प्रशासन के इशारों पर नाच रहीं हैं। क्योंकि इस फर्जीवाड़े की संपूर्ण जानकारी स्कूल प्रशासन को है और स्कूल प्रशासन उनपर कार्रवाई ना करके उनका उपयोग अपने द्वारा किए जा रहे ग़लत कार्यों में सहयोग करने के लिए कर रहीं हैं जोकि स्कूल प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जिम्मेदार पद पर बैठे लोग किस तरह इस भ्रष्टाचार में अपना लाभ निकालने में लगे हुए हैं। यह स्थिति यही नहीं रूकती है ऐसी जानकारी मिली है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2023 में भी ईसी तरह का खेल खेला गया था और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर पैसों का लेनदेन कर भर्ती किया गया है।

14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैठक सम्पन्न

आबट्रशन, चक बाउस एव बीमा-बैंक प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण पर हुआ मंथन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

वर्ष 2026 की प्रथम नेशनल लोक अदालत, जो कि 14 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी, के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से आर्बिट्रेशन, चेक बाउंस, क्लेम/बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं तथा बैंक एवं फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।यह बैठक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के आदेशानुसार सरोज नंद दास, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में देवेन्द्र कुमार, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मोहित सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अनिता कोशिमा रावटे, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान आर्बिट्रेशन, चेक बाउंस तथा क्लेम/बीमा कंपनी से संबंधित लंबित प्रकरणों में पक्षकारों के साथ प्री-सिटिंग आयोजित कर आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। यह भी कहा गया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में समाधान संभव है, जिससे न्यायालयों पर भार भी कम होता है। बैठक में बैंक एवं फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत करें। साथ ही समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का पंजीयन, नोटिस की तामिली सुनिश्चित करने एवं पक्षकारों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीनामा करने पर विशेष जोर दिया गया।उक्त बैठक में आर्बिट्रेशन एवं क्लेम/बीमा कंपनी के अधिवक्तागण, लीड बैंक, विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक, तथा फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी उपस्थितजनों ने आगामी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया।

बजट से छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास को मिलेगी उड़ान : श्रीनिवास राव मद्दी

बीजापुर/मूक पत्रिका

विधानसभा प्रभारी श्रीनिवास राव मद्दी ने बिते रविवार को प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के बजट को छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह बजट नवोत्थान और वैश्विक भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें केवल आंकड़े नहीं, बल्कि विकसित भारत-2047 का स्पष्ट विजन भी नजर आता है। मद्दी ने बजट प्रावधानों की सराहना करते हुए इसे महज वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि अगले 25 वर्षों के विकास का मार्गदर्शक बताया। उनका कहना था कि खनिज संपदा से समृद्ध बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के जिलों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। बजट को तीन प्रमुख कर्तव्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएंगे। साथ ही 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने से आने वाले पांच वर्षों की विकास दिशा तय होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि बजट के लक्ष्यों से बिजली, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में तेजी आएगी और यह समावेशी विकास की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा।प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, जिला महामंत्री संजय लुक्कड़, फूलचंद गागड़ा, जिला उपाध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर, एसटी मोर्चा प्रदेश मंत्री राम राना, मंडल अध्यक्ष अशोक राव और पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जागर लक्षमैय्या सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

वृद्धजनों के सम्मान से ही सशक्त समाज का निर्माण : विजय सिन्हा

डीजनीलैंड में वृद्धजनों के सम्मान में गरिमामय समारोह आयोजित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

नगर के डीजनीलैंड परिसर में वृद्धाआश्रम से पधारे वृद्धजनों के सम्मान में एक भावपूर्ण एवं गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में अध्यक्ष सिन्हा ने कहा कि ÷वृद्धजन हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव, संस्कार और मार्गदर्शन से ही समाज की मजबूत नींव तैयार होती है। आज हम जिस भी मुकाम पर हैं, उसमें हमारे बुजुर्गों का त्याग, तपस्या और योगदान निहित है। उनका सम्मान करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है।÷उन्होंने आगे कहा कि वृद्धजनों के सम्मान, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ÷समाज तभी सशक्त बनेगा जब हम अपने बुजुर्गों को आदर, समय और सहयोग देंगे।÷कार्यक्रम के अंत में श्री सिन्हा ने सभी सम्मानित वृद्धजनों के दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की कामना करते हुए आयोजकों को इस सराहनीय पहल के लिए बधाई दी।समारोह में डीजनीलैंड स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती दीपा तिवारी, किसान नेता हर्ष तिवारी, सभापति नीतू कोठारी, योगेश वर्मा, समाजसेविका रानी रवानी, भाग्य श्री पोल सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं वृद्धजन उपस्थित रहे।कार्यक्रम में वृद्धजनों का सम्मान कर समाज में उनके प्रति संवेदनशीलता और आदर का संदेश दिया गया।

आवापल्ली में विकासखंड स्तरीय स्वस्थ पंचायत सम्मेलन संपन्न

बीजापुर/मूक पत्रिका

विकासखंड उसूर के आवापल्ली में 6 फरवरी को स्वस्थ पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कलेक्टर संबित मिश्रा के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे व सीएमएचओ डॉ. बी.आर. पुजारी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीणों की अच्छी भागीदारी रही। सम्मेलन के दौरान ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के सदस्यों ने जागरूकता रैली निकालकर ग्रामीणों को स्वच्छता, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उनके बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली मितानिनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया, जबकि मोबाइल एकेडमी कोर्स पूरा करने वाली मितानिनों को प्रमाण-पत्र दिए गए। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। विभिन्न विभागों से जुड़े करीब 132 आवेदन प्राप्त हुए।

जनपद पंचायत उसूर की अध्यक्ष पूर्णिमा तेलम की अध्यक्षता में आयोजित यह सम्मेलन दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गांवों में स्वास्थ्य और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

नारंगी नदी किनारे तटरक्षण कार्य शुरू, किसानों को मिलेगी राहत

298 लाख की योजना का सांसद महेश कश्यप ने किया शुभारंभ

जगदलपुर/मूक पत्रिका

बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जमीन को नदी कटाव से बचाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। जल संसाधन विभाग की ओर से ग्राम भैसगांव के पास नारंगी नदी पर 298.02 लाख रुपये की लागत से बनने वाले तटरक्षण कार्य का भूमिपूजन बस्तर सांसद महेश कश्यप ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ दंतेश्वरी और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुई। ग्रामीणों ने सांसद का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। काम शुरू होने की खबर से इलाके में खुशी देखी गई और लोगों ने इसे लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान बताया।

सांसद महेश कश्यप ने कहा कि हर साल बारिश में नारंगी नदी किनारे बसे गांवों के लोग बाढ़ की चिंता में रहते थे। कई बार फसलें बर्बाद होती थीं और घरों पर भी खतरा मंडराता था। तटरक्षण बनने से खेती की जमीन सुरक्षित होगी और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। जनपद पंचायत अध्यक्ष संतोष बघेल ने कहा कि यह काम क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग थी। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष सुखदेव मंडावी ने इसे ग्रामीण विकास के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि ऐसे निर्माण कार्य गांवों को मजबूत बनाते हैं।भूमिपूजन कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य शकुंतला कश्यप, जनपद उपाध्यक्ष जयवती कश्यप, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, सरपंच मदन बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा स्वामी डीबी कार्प लिमिटेड के लिए प्लाट नम्बर 40/44 इंडस्ट्रियल एरिया बीरगांव रोड, उरला, रायपुर से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।